स्वदेशी पत्रिका

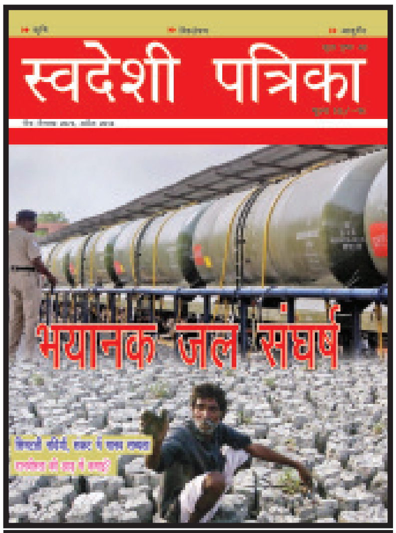

वर्ष–24, अंक–4

चैत्र–बैशाख 2072, अप्रैल 2016

संपादक

विक्रम उपाध्याय

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज 39

कवर चतुर्थ पेज 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

भयानक जल संघर्ष

निधि कुलपति

1 कवर पेज

2 कवर द्वितीय पेज

08 आवरण कथा–2
सिमटती नदियाँ, संकट में मानव सभ्यता
.... पंकज चतुर्वेदी

10 आवरण कथा–3
संशय में है नदी जोड़ योजना की कामयाबी
.... ज्ञानेन्द्र रावत

12 आवरण कथ–4
जीवनदायिनी यमुना मृत अवस्था की ओर
.... सुन्दर वसौया

15 मुद्दा
विजय माल्या: कानून को छकाने की कोशिश
.... विक्रम उपाध्याय

17 कृषि
उद्योगों जैसा हो कृषि राहत पैकेज
.... देविंदर शर्मा

19 स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूचि

23 विश्लेषण
दानवीरता की आड़ में कमाई?
.... डॉ. अश्वनी महाजन

25 कानून
'आधार' बनें पारदर्शिता का आधार
.... डॉ. सुभाष शर्मा

27 विश्व व्यापार संगठन
डब्लूटीओ पर पुर्नविचार जरूरी
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

29 व्यक्तित्व
स्वातंत्र्य वीर सावरकर: व्यक्तित्व एवं कृतित्व
.... डॉ. विजय वशिष्ठ

32 आयुर्वेद
आयुर्वेद: स्वस्थ्य एवं दीघार्यु जीवन पद्धति
.... स्वदेशी संवाद

पाठकनामा

असम से उम्मीद

बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे देश में धीरे–धीरे अपने अड्डे बना लिए है। घरों में काम के साथ–साथ अब मजदूरों के काम काज को भी छीनने लगे है। देश में वैसे ही रोजगार के अवसर कम है, ऐसे में घुसपैठिये आकर हमारे लिए और मुसीबत पैदा कर रहे हैं। असम में चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि भारत में भारतीयों को सम्मान मिलेगा या विदेशी आकर हमारे अधिकारों का हनन करते रहेंगे। उम्मीद है कि असम से एक नया रास्ता निकलेगा। सवाल सिर्फ रोजगार के अवसरों को निगलने का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर भी है। दिल्ली में भी बांग्लादेशी हर तरह के अपराध में लिप्त है। उम्मीद है कि असम का चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक सबक होगा।

नीरज भारद्वाज, *शाहदरा, दिल्ली*

*****

काला धन पर कोई अंकुश नहीं

मोदी सरकार को आए दो वर्ष हो गए, लेकिन काला धन को वापिस लाने के मुद्दे पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। उल्टे पनामा पेपर लिक्स ने यह बताया कि अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे है जिनका धन विदेशों में जमा है और वे आराम से इस देश में बिना किसी डर–भय के रह रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक पनामा पेपर लिक्स के दायरे में है। उन्होंने अपनी जनता से माफी भी मांगी है। लेकिन भारत में अभी तक किसी ने भी विदेशों में धन जमा होने की बात स्वीकारी नहीं है। अब सारा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पर है। वह जितना शीघ्र इस मामले में कदम उठायेंगे, उतना ही जनता का विश्वास उनकों हासिल होगा। देरी या हील हवाला से जनता के मन में आशंका पैदा होगी, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पहले ही वित्तमंत्री अरूण जेटली यह घोषणा कर चुके है कि नई जानकारी के आधार पर जांच के लिए एक बहुस्तरीय कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन इस कमेटी की जांच की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

मनोज कुलियाल, *उत्तराखंड*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

ममता दिल्ली आती हैं तो सोनिया गांधी से मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने में उनको संकोच होता है।

नरेन्द्र मोदी

बंगाल चुनाव में

मैं प्रधानमंत्री की गुलाम नहीं हूं।

ममता बनर्जी

बंगाल चुनाव प्रचार में

पनामा पेपर की जांच नतीजे के बाद कांग्रेस जश्न नहीं मना पायेगी।

अरूण जेटली

वित्तमंत्री

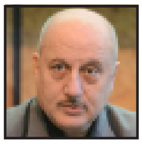

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया गया। क्षीर भवानी का दर्शन क्यों नहीं करने दिया गया।

अनुपम खेर

अभिनेता

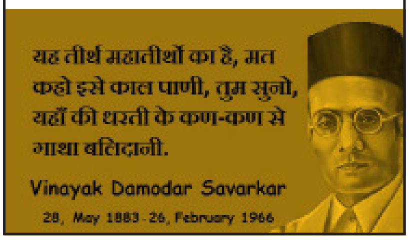

संपादकीय

कालेधन पर गंभीरता जरूरी

एक अंग्रेजी अखबार ने जब पनामा की एक कानूनी सलाहकार कंपनी द्वारा बनाई गई दुनिया भर के प्रमुख लोगों की फर्जी कंपनियों की सूची जारी की तो एक बार फिर से हंगामा मच गया। अभी कुछ समय पहले ही ऐसी ही सूची स्वीस बैंक के हवाले से भी जारी की गई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने उस सूची पर गंभीरता दिखाते हुए एक विशेष कार्यदल का गठन भी कर दिया गया था। ताकि विदेशों में जमा हुए उस धन का पता लगाया जा सके जो चोरी छिपे, बिना कर चुकाए भारतीयों ने विदेशों में ले जाकर जमा कर दिये थे। अभी तक उस सूची का क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची, किन–किन लोगों के खातों के बारे में ठीक–ठीक पता लगाया जा सका, ऐसी कोई जानकारी आम जनता को हासिल नहीं हुई है। अब पनामा पेपर लिक्स में लगभग 500 ऐसे भारतीयों की सूची आई है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों ने भारत से पैसे ले जाकर उन देशों में जमा कराये है जहां किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता और न ही उनके जमा धन के बारे में किसी को कोई जानकारी दी जाती है। पनामा पेपर लिक्स के बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिन नामों की सार्वजनिक रूप से खाता खोले वालों के रूप में पहचान की जा रही है, वे खाते उन्हीं के हो। महानायक अमिताभ बच्चन खुद इसी तरह का कुछ दावा कर रहे है। उनका कहना है कि पनामा पेपर लिक्स के जरिये जिन कंपनियों के निदेशक होने का आरोप मुझ पर लगा है दरअसल उन कंपनियों से कभी भी उनका लेना–देना नहीं रहा है। अमिताभ बच्चन ने यहीं कहा है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रिश्तेदार और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जब यह स्वीकार करते है कि पनामा पेपर लिक्स में शामिल उनके नाम सही है और सचमुच उनके खाते उन देशों में है जिन्हें हम 'टैक्स हैवंस' के नाम से जानते है, तो उसी पनामा पेपर लिक्स को झुठलाना भारतीयों के संदर्भ में ठीक नहीं लगता। अब फिर से यह सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या पहले से चल रही जांच की तरह पनामा पेपर लिक्स में शामिल नामों पर उसी तरह का रवैया अपनाया जायेगा, जैसा अब तक काले धन के मामले में अपनाया जाता रहा है। वित्तमंत्री अरूण जेटली पहले की तरह फिर ये दावें करते नजर आ रहे है कि किसी को भी बख्सा नहीं जायेगा। उन्होंने आयकर, प्रवर्तन निदेशालय समेत कई वित्तीय मामलों की खुफिया एजेंसियों को शामिल कर एक जांच कमेटी बना दी है, जो पनामा पेपर लिक्स के शामिल नामों के बारे में और उनके कथित विदेशी खातों के बारे में जांच करेगी। अब इस जांच पर भरोसा कैसे किया जाए? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार ज्यादा संजीदा तरीके से इस मामले में कदम उठाना चाहते है। उन्होंने संभवत् यह निर्देश दिया है कि इस बहुस्तरीय जांच कमेटी की पहली रिपोर्ट तय समय सीमा में आनी चाहिए। अब यह समय सीमा 15 से 30 दिन तक हो सकती है। लेकिन अभी से ही इस जांच को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। अंबानी से लेकर अड़ानी तक के रिश्तेदारों के नाम इस पनामा पेपर लिक्स में शामिल है। बालीवुड़ से लेकर भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख लोगों तक जांच की आंच पहुंच सकती है। यदि जांच में अनावश्यक देरी हुई तो विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जायेगा कि सरकार से नजदीकी वाले औद्योगिक घराने को संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस अभी से ही प्रधानमंत्री मोदी और वित्तमंत्री अरूण जेटली पर कटाक्ष कर रही है। हालांकि अरूण जेटली ने यह बयान दिया है कि पनामा पेपर लिक्स की जांच सामने आने के बाद कांग्रेस जश्न नहीं मना पायेगी। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि पनामा पेपर लिक्स से जानबूझकर राजनीतिज्ञों के नाम हटा दिए गए है। यह आश्चर्यजनक ही बात है कि पनामा पेपर लिक्स में किसी भी बड़े भारतीय राजनीतिज्ञ का नाम सामने नहीं आया है। जबकि अभी तक यहीं माना जा रहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीतिज्ञों ने ही देश से बाहर धन भेजा है और भारी मात्रा में काला धन जमा किया है। आम चुनाव में काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे बाद में जुमला कहकर उसका मजाक उड़ा दिया गया। पनामा पेपर लिक्स के जरिये एक बार फिर मुद्दा गंभीरता के साथ हमारे सामने आया है। इस बार सरकार को पूरी तत्परता दिखानी चाहिए।

भयानक जल संघर्ष

सूखे की मार की खबरें देशभर से आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी के लिए घंटों से लगी लंबी कतारें लग रही हैं। ठाणे और आसपास के इलाकों में हर हफ्ते 60 घंटे पानी की कटौती शुरू हो गई है।

– **निधि कुलपति**

आजाद भारत के इतिहास में सबसे खराब सूखा है इस बार। जब दक्षिण एशिया में बांधों के विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर ने कहा भी कि... 'तो इस बार पानी की किल्लत की भयावह स्थिति कुछ समझ में आयी।' सुप्रीम कोर्ट भी सूखे को लेकर चिंतित है। उसने लगातार केंद्र के ढीले रवैये को लेकर सवाल उठाए। यहां तक पूछा कि सूखे की हालत को लेकर आप गंभीर हैं भी या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि सूखे का प्रभाव 12 राज्यों में है और 10 राज्य सूखाग्रस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकर और राज्य सरकारों को फटकार लगाई। हरियाणा, बिहार और गुजरात को भी खरी–खरी सुनाई कि जब कम बारिश से किसान जूझ रहे हैं तो सही तथ्य पेश क्यों नहीं करते और खुद को सूखाग्रस्त घोषित करते? कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीने का पानी, पशु, फसल से लेकर कई अहम मुद्दे हैं जिन पर केंद्र को जवाब दे।

सूखे की मार की खबरें देशभर से आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी के लिए घंटों से लगी लंबी कतारें लग रही हैं। ठाणे और आसपास के इलाकों में हर हफ्ते 60 घंटे पानी की कटौती शुरू हो गई है। बच्चे स्कूल से जल्दी आ रहे हैं पानी भरने में मदद करने के लिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी पानी की भारी किल्लत है। अब पानी के लिए झगड़े होने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में 2015 में ही 3,228 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। मराठवाड़ा में पिछले 4 सालों से पानी की किल्लत है। पानी बंटने की जगहों पर धारा 144 लागू है।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पानी की सुरक्षा के लिए बंदूकधारी सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई है। पानी की चोरी रोकने के लिए जामनी नदी पर ये लोग 24 घंटे पहरेदारी कर

रहे हैं। पिछले तीन सालों से बुंदेलखंड में पानी की भारी किल्लत है जिसके इलाके उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। चोरी रोकने लिए नगरपालिका ने सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। बान्दा में से हर 10 में से 7 परिवार पलायन कर रहे है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया अपने भूजल के लिये जाना जाता था। 10 साल पहले तक यहां पानी 20 फीट की गहराई में मिल जाता था और अब 140 फीट पर मिल रहा है। बुन्देलखंड के कुछ इलाकों में तो इस बार रबी की फसल बोई ही नहीं गई। कृषि उत्पाद आधे हो गये हैं। उड़ीसा में किसानों ने सार्वजनिक तटबंधों को तोड़कर अपनी फसलों को सींच रहे हैं।

कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध सूख चुका है जिससे बेंगलुरु समेत कई इलाकों में पानी का संकट गहरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 91 बड़े जलाशयों में पानी का स्तर पिछले 10 सालों में सबसे कम है, 29 प्रतिशत से भी कम। उनकी देशभर के जलाशयों पर रिपोर्ट के अनुसार पूर्व के जलाशयों में 44 प्रतिशत, मध्य भारत के इलाकों में 36 प्रतिशत, दक्षिण भारत में 20 प्रतिशत, पश्चिमी इलाकों में 26 प्रतिशत और उत्तर के जलाशयों में 27 प्रतिशत पानी है। सवाल सूखाग्रत राज्यों को कम फंड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां महाराष्ट्र को अब तक राहत खर्च का सिर्फ 25 प्रतिशत दिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा,

- **मराठवाड़ा के सूखा ग्रस्त इलाकों खासकर नांदेड और लातूर से किसानों और खेतिहर मजदूरों का मुंबई आना शुरू**
- **उत्तर प्रदेश के 50 जिलें सूखाग्रस्त घोषित, जहां 60 फीसदी से कम बारिश।**
- **अमेरिकी एजेंसी का दावा इस साल भारत में बड़ा अकाल पड़ सकता है।**
- **बुंदेलखंड में सूखे की भीषण स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।**
- **केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूखे से निपटने के लिए 12 हजार 230 करोड़ रुपये जारी किए।**
- **पानी की उपलब्धता का आकलन करने और एकत्रित सूचना के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की टीम को पूरे देश में भेजा।**

तेलंगाना को 8 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ को 24 प्रतिशत दिया गया है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनरेगा के तहत वो एक हफ्ते में 11,030 करोड़ राज्य सरकारों को देगी। 7983 करोड़ मेहनताना बकाया है। सूखा प्रभावित राज्यों में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए 50 दिन का अतिरिक्त काम दिया जायेगा। बकाया 3686 करोड़ का भी है जो मनरेगा के लिए प्रयोग में लाये गये सामान का है। सवाल मनरेगा के तहत कम काम देना और वेतन में देरी पर भी उठ रहे हैं। 2015–16 में मनरेगा के तहत औसतन 47.8 दिन काम दिया गया, जबकि प्रावधान 100 दिन का है। 100 दिन का काम देश भर में सिर्फ 4.8 प्रतिशत लोगों को ही दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2 प्रतिशत, छत्तीसगढ में 3.7 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 4.5 प्रतिशत, उड़ीसा में 4.6 प्रतिशत, कर्नाटक में 5.5 प्रतिशत। हालांकि महाराष्ट्र में में 12.2 प्रतिशत, तेलगाना में 7.3 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 8 और झारखण्ड में 8.2 प्रतिशत दिया गया। काम भी इतना कम और उस पर मेहनताना भी देरी से, समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रही है हमारे ग्रामीण भारत में रह रहे लोगों की। न पैसा न पानी, इस स्थिति से निवारण के लिए युद्ध स्तर पर पानी को सहेजने की जरुरत है.....सोचें और सहेजें पानी को! ❑❑

लेखक एनडीटीवी इंडिया में सीनियर एडिटर हैं

सिमटती नदियाँ, संकट में मानव सभ्यता

बहुत पुरानी बात है, हमारे देश में एक नदी थी सिंधु। इस नदी की घाटी में खुदाई हुई तो मोहन जोदड़ों नाम का शहर मिला, ऐसा शहर जो बताता था कि हमारे पूर्वजों के पूर्वज बेहद सभ्य व सुसंस्कृत थे और नदियों से उनका शरीर–श्वांस का रिश्ता था। नदियों के किनारे समाज विकसित हुआ, बस्ती, खेती, मिट्टी व अनाज का प्रयोग, अग्नि का इस्तेमाल के अन्वेषण हुए।

मन्दिर व तीर्थ नदी के किनारे बसे, ज्ञान व आध्यात्म का पाठ इन्हीं नदियों की लहरों के साथ दुनिया भर में फैला। कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक व भावात्मक एकता का सम्वेत स्वर इन नदियों से ही उभरता है। इंसान मशीनों की खोज करता रहा, अपने सुख–सुविधाओं व कम समय में ज्यादा काम की जुगत तलाशता रहा और इसी आपाधापी में सरस्वती जैसी नदी गुम हो गई। गंगा व यमुना पर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया।

बीते चार दशकों के दौरान समाज व सरकार ने कई परिभाषाएँ, मापदण्ड, योजनाएँ गढ़ीं कि नदियों को बचाया जाये, लेकिन विडम्बना है कि उतनी ही तेजी से पावनता और पानी नदियों से लुप्त होता रहा।

बीते चार दशकों के दौरान समाज व सरकार ने कई परिभाषाएँ, मापदण्ड, योजनाएँ गढ़ीं कि नदियों को बचाया जाये, लेकिन विडंबना है कि उतनी ही तेजी से पावनता और पानी नदियों से लुप्त होता रहा।

– पंकज चतुर्वेदी

हमारे देश में 13 बड़े, 45 मध्यम और 55 लघु जलग्रहण क्षेत्र हैं। जलग्रहण क्षेत्र उस सम्पूर्ण इलाके को कहा जाता है, जहाँ से पानी बहकर नदियों में आता है। इसमें हिमखण्ड, सहायक नदियाँ, नाले आदि शामिल होते हैं।

जिन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र 20 हजार वर्ग किलोमीटर से बड़ा होता है, उन्हें बड़ा–नदी जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। 20 हजार से दो हजार वर्ग किलोमीटर वाले को मध्यम, दो हजार से कम वाले को लघु जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इस मापदण्ड के अनुसार गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, कावेरी, पेन्नार, माही, ब्राह्मणी, महानदी और साबरमति बड़े जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियाँ हैं। इनमें से तीन नदियाँ – गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय के हिमखण्डों के पिघलने से अवतरित होती हैं। इन सदानीरा नदियों को

'हिमालयी नदी' कहा जाता है। शेष दस को पठारी नदी कहते हैं, जो मूलतः वर्षा पर निर्भर होती हैं।

यह आँकड़ा वैसे बड़ा लुभावना लगता है कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि सभी नदियों का सम्मिलित जलग्रहण क्षेत्र 30.50 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय नदियों के मार्ग से हर साल 1645 घन किलोलीटर पानी बहता है जो सारी दुनिया की कुल नदियों का 4.445 प्रतिशत है। आँकड़ों के आधार पर हम पानी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि पूरे पानी का कोई 85 फीसदी बारिश के तीन महीनों में समुद्र की ओर बह जाता है और नदियाँ सूखी रह जाती हैं।

नदियों के सामने खड़े हो रहे संकट ने मानवता के लिये भी चेतावनी का बिगुल बजा दिया है, जाहिर है कि बगैर जल के जीवन की कल्पना सम्भव नहीं है। हमारी नदियों के सामने मूलरूप से तीन तरह के संकट हैं – पानी की कमी, मिट्टी का आधिक्य और प्रदूषण।

धरती के तापमान में हो रही बढ़ोत्तरी के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है और इसी का परिणाम है कि या तो बारिश अनियमित हो रही है या फिर बेहद कम। मानसून के तीन महीनों में बमुश्किल चालीस दिन पानी बरसना या फिर एक सप्ताह में ही अन्धाधुन्ध बारिश हो जाना या फिर बेहद कम बरसना, ये सभी परिस्थितियाँ नदियों के लिये अस्तित्व का संकट पैदा कर रही हैं।

बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी और ब्राह्मणी के रास्तों में पानी खूब बरसता है और इनमें न्यूनतम बहाव 4.7 लाख घनमीटर प्रति वर्गकिलोमीटर होता है। वहीं कृष्णा, सिंधु, तापी, नर्मदा और गोदावरी का पथ कम वर्षा वाला है सो इसमें जल बहाव 2.6 लाख घनमीटर प्रति वर्गकिलोमीटर ही रहता है। कावेरी, पेन्नार, माही और साबरमति में तो बहाव 0.6 लाख घनमीटर ही रह जाता है। सिंचाई व अन्य कार्यों के लिये नदियों के अधिक दोहन, बाँध आदि के कारण नदियों के प्राकृतिक स्वरूपों के साथ भी छेड़छाड़ हुई व इसके चलते नदियों में पानी कम हो रहा है।

नदियाँ अपने साथ अपने रास्ते की मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े व बहुत सा खनिज बहाकर लाती हैं। पहाड़ी व नदियों के मार्ग पर अन्धाधुन्ध जंगल कटाई, खनन, पहाड़ों को काटने, विस्फोटकों के इस्तेमाल आदि के चलते थोड़ी सी बारिश में ही बहुत सा मलबा बहकर नदियों में गिर जाता है।

परिणामस्वरूप नदियाँ उथली हो रही हैं, उनके रास्ते बदल रहे हैं और थोड़ा सा पानी आने पर ही वे बाढ़ का रूप ले लेती हैं। यह भी खतरनाक है कि सरकार व समाज इन्तजार करता है कि नदी सूखे व हम उसकी छोड़ी हुई जमीन पर कब्जा कर लें। इससे नदियों के पाट संकरे हो रहे हैं उसके करीब बसावट बढ़ने से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है।

आधुनिक युग में नदियों को सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण से है। कल–कारखानों की निकासी, घरों की गन्दगी, खेतों में मिलाए जा रहे रासायनिक दवा व खादों का हिस्सा, भूमि कटाव, और भी कई ऐसे कारक हैं जो नदी के जल को जहर बना रहे हैं। **अनुमान है कि जितने जल का उपयोग किया जाता है, उसके मात्र 20 प्रतिशत की ही खपत होती है, शेष 80 फीसदी सारा कचरा समेटे बाहर आ जाता है। यही अपशिष्ट या माल–जल कहा जाता है, जो नदियों का दुश्मन है। भले ही हम कारखानों को दोषी बताएँ, लेकिन नदियों की गन्दगी का तीन चौथाई हिस्सा घरेलू मल–जल ही है।**

आज देश की 70 फीसदी नदियाँ प्रदूषित हैं और मरने के कगार पर हैं। इनमें गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, हरियाणा की मारकंडा, मप्र की खान, उप्र की काली और हिण्डन, आन्ध्र की मुंसी, दिल्ली में यमुना और महाराष्ट्र की भीमा मिलाकर 10 नदियाँ सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं।

हालत यह है कि देश की 27 नदियाँ नदी के मानक में भी रखने लायक नहीं बची हैं। वैसे गंगा हो या यमुना, गोमती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, चेनाब, रावी, व्यास, पार्वती, हरदा, कोसी, गंडगोला, मसैहा, वरुणा, बेतवा, ढौंक, डेकन, डागरा, रमजान, दामोदर,

सुवर्णरेखा, सरयू, रामगंगा, गौला, सरसिया, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, गंडक, कमला, सोन एवं भगीरथी या फिर इनकी सहायक, कमोबेश सभी प्रदूषित हैं और अपने अस्तित्व के लिये जूझ रही हैं।

दरअसल पिछले 50 बरसों में अनियंत्रित विकास और औद्योगीकरण के कारण प्रकृति के तरल स्नेह को संसाधन के रूप में देखा जाने लगा, श्रद्धा–भावना का लोप हुआ और उपभोग की वृत्ति बध्ती चली गई। चूँकि नदी से जंगल, पहाड़, किनारे, वन्य जीव, पक्षी और जन–जीवन गहरे तक जुड़ा है, इसलिये जब नदी पर संकट आया, तब उससे जुड़े सभी सजीव–निर्जीव प्रभावित हुए बिना न रहे और उनके अस्तित्व पर भी संकट मँडराने लगा। असल में जैसे–जैसे सभ्यता का विस्तार हुआ, प्रदूषण ने नदियों के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया।

राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, नागपुर की एक रपट बताती है कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी सहित देश की 14 प्रमुख नदियों में देश का 85 प्रतिशत पानी प्रवाहित होता है। ये नदियाँ इतनी बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी हैं कि देश की 66 फीसदी बीमारियों का कारण इनका जहरीला जल है। इस कारण से हर साल 600 करोड़ रुपए के बराबर सात करोड़

संशय में है नदी जोड़ योजना की कामयाबी

– ज्ञानेन्द्र रावत –

आखिरकार मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी केन–बेतवा नदी–जोड़ परियोजना अब संकट में है। गौरतलब है पिछले साल मोदी सरकार ने नदी–जोड़ योजना के क्रम में सबसे पहले केन–बेतवा पर ही काम शुरू करने का फैसला लिया था। जैसी आशा थी कि पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी मिलने और इस इलाके में बसे गाँवों के लोगों द्वारा विस्थापन पर अपनी सहमति देने के बाद देश की पहली केन–बेतवा परियोजना पर साल 2015 के आखिर तक काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा सम्भव न हो सका। हाँ इतना जरूर हुआ कि इससे पहले इसमें एक और पंचेश्वर परियोजना शामिल हो गई। इस बारे में माना जा रहा था कि लगभग 7600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 4.46 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई की जा सकेगी। अब यह परियोजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के कारण लटकी पड़ी है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में शारदा–घाघरा–गोमती को जोड़ने की योजना पर शीघ्र ही कार्य शुरू होने जा रहा है।

कहा यह जा रहा है कि इससे पूर्वी उ.प्र. में सिंचाई व्यवस्था और मजबूत होगी। यही नहीं इस इलाके को बाढ़ से हमेशा के लिये निजात मिल जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे बरसाती नदी का रूप ले चुकी गोमती को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसमें साल भर पानी का स्तर सामान्य रहेगा।

गोमती में पानी की समस्या नहीं रहेगी और इसके किनारे बसे लखनऊ शहर की पेयजल समस्या भी दूर हो जाएगी। अब केन्द्रीय जल आयोग के ऊपर यह दारोमदार है कि वह कब तक परियोजना का सर्वेक्षण करवाकर डीपीआर दे पाता है या नहीं। दरअसल देश में नदी जोड़ परियोजना के औचित्य पर बाजपेयी सरकार के समय से ही सवाल उठते रहे हैं।

इस योजना को कभी भी किसी भी कीमत पर लाभकारी नहीं माना गया। योजना आयोग भी इसे अदूरदर्शी व अव्यावहारिक की संज्ञा दे चुका है। हमारे पर्यावरणविदों ने तो बाजपेयी सरकार के समय ही इसका पुरजोर विरोध किया था। पर्यावरण की दृष्टि से उन्होंने इसे खतरनाक बताया था।

पर्यावरणविद अनुपम मिश्र ने उस समय कहा था, 'प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ के भयानक परिणाम होंगे। नदियों को जोड़ने के लिये जो नहरें बनेंगी, उनके रास्ते में ढेर सारे जंगल, अभयारण्य, गाँव, खेत आदि आएँगे। उनको उजाड़ना न पर्यावरण की दृष्टि से उचित होगा, न सामाजिक दृष्टि से। इससे सारी व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाएगी और जो समस्याएँ पैदा होंगी, उनसे पार पाना आसान नहीं होगा।' लेकिन सारे विरोध को दरकिनार कर मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही नदियों को जोड़ने वाली इस परियोजना को शुरू करने का मन बना लिया। गौरतलब है कि बाजपेयी शासन के दौरान इसके दूरगामी परिणामों–लाभों के बारे में बढ़ा–चढ़ा कर ढेरों दावे किये गए थे। आज भी कहा जा रहा है जल संकट का निवारण ही इस योजना का लक्ष्य है। जल संकट से हमें कहाँ तक छुटकारा मिल पाएगा, यह तो समय ही बताएगा।

सच यह है कि प्रकृति मानवीय नियमों से नहीं, खुद बनाए नियमों से संचालित होती है। वर्तमान में प्रकृति हो या उसके नियम, उनमें मानवीय दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के दुष्परिणाम सबके

तीस लाख मानव दिवसों की हानि होती है।

अभी तो देश में नदियों की सफाई नारों के शोर और आँकड़ों के बोझ में दम तोड़ती रही हैं। बड़ी नदियों में जाकर मिलने वाली हिण्डन व केन जैसी नदियों का तो अस्तित्व ही संकट में है तो यमुना कहीं लुप्त हो जाती है व किसी गन्दे नाले के मिलने से जीवित दिखने लगती है। सोन, जोहिला, नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से ही नदियों के दमन की शुरुआत हो जाती है तो कही नदियों को जोड़ने व नहर से उन्हें जिन्दा करने के प्रयास हो रहे हैं। नदी में जहर केवल पानी को ही नहीं मार रहा है, उस पर आश्रित जैव संसार पर भी खतरा होता है। नदी में मिलने वाली मछली केवल राजस्व या आय का जरिया मात्र नहीं है, यह जल प्रदूषण दूर करने में भी सहायक होती हैं।

जल ही जीवन का आधार है, लेकिन भारत की अधिकांश नदियाँ शहरों के करोड़ों लीटर जल–मल व कारखानों से निकले जहर को ढोने वाले नाले का रूप ले चुकी हैं। नदियों में शव बहा देने, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने या उसकी दिशा बदलने से हमारे देश की असली ताकत, हमारे समृद्ध जल–संसाधन नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ❑❑

सामने हैं। नदी जोड़ परियोजना मानवीय हस्तक्षेप का ही प्रतीक है। प्रकृति नदी का मार्ग खुद तय करती है।

नदी का बेसिन उसकी घाटी होती है जिसमें उसका जल होता है। प्रकृति प्रदत्त नदियों को जोड़ने से प्रकृति का सन्तुलन गड़बड़ा जाएगा। इससे विस्थापन की समस्या कितनी विकराल हो जाएगी, इसका अन्दाजा सरकार और नीति–नियन्ताओं को नहीं है। भाखड़ा–हरसूद को हम आज भी भूल नहीं पाये हैं। भाखड़ा–नांगल बाँध के समय के विस्थापितों की रिपोर्ट खुलासा करती है कि आज भी अनेकों ऐसे विस्थापित परिवार मौजूद हैं जो पुर्नवास की बाट जोह रहे हैं।

उस हालत में देश की डेढ़ दर्जन नदियों को जोड़ने से उत्पन्न लाखों लोगों के विस्थापन, उनके जान–माल की भरपाई और पुर्नवास की व्यवस्था सरकार कैसे कर पाएगी, यह समझ से परे है। जबकि सिंचाई की अनेकों बड़ी परियोजनाओं से कितनी आबादी उजड़ी, सैकड़ों–हजारों गाँवों की बलि चढ़ी, से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण से मौसम में बदलाव आया, मानसून की गति बिगड़ी, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि से देश दोचार हुआ। लेकिन इस ओर भी हमने सोचना मुनासिब नहीं समझाा।

अच्छा होता सरकार भूजल के अन्धाधुन्ध दोहन के खिलाफ कानून बनाती, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन कराती, वर्षाजल को बेकार समुद्र में बहकर जाने से रोकने, उसके संरक्षण के उपाय करती और पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में जन–चेतना जागृत करती। लेकिन ऐसा करने के बजाय पानी के व्यापार को बढ़ाने वाली नदी–जोड़ परियोजना को लागू करने का विचार कहाँ तक न्यायोचित है, यह विचार का मुद्दा है?

हमारे योजनाकारों ने इस ओर भी ध्यान क्यों नहीं दिया कि गंगा और यमुना आसपास से ही निकल कर अलग–अलग क्यों बहती हैं। फिर जिस प्रभु ने इतनी सारी नदियाँ बनाईं, उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नदीं क्यों नहीं निकाली। आखिर एक ही उद्गम से निकलकर नदियाँ अलग–अलग क्यों बहती हैं? समझ नहीं आता इस योजना में ऐसा क्या है जिस पर अमल के लिये सरकार अडिग है। विडम्बना यह कि पारतापी–नर्मदा व दमनगंगा–पिंजाल को लेकर महाराष्ट्र व गुजरात में एक ही दल की सरकारें होने के बाद भी विवाद जारी है। राज्यों के बीच जल–विवाद थमे नहीं हैं।

महानदी–गोदावरी नदी–जोड़ परियोजना पर ओडिशा का विरोध जगजाहिर है। पहले से तय की गईं 30 नदी–जोड़ परियोजनाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान देश में शारदा–यमुना लिंक के रूप में 31वीं परियोजना भी जुड़ गई है। इसके पानी को उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात तक पहुँचाने की योजना है। उस हालत में जबकि हिमालयी इलाके की सात परियोजनाओं पर दूसरे देशों के शामिल होने और मैदानी इलाकों की नौ परियोजनाओं में राज्यों में आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण रोक लगी हुई है।

केन–बेतवा अभी अधर में है जबकि शारदा–घाघरा और गोमती को जोड़ने की परियोजना के पहले चरण को जल संसाधन मंत्रालय हरी झंडी दे चुका है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि हकीकत है कि मैदानी इलाकों की परियोजनाओं के परवान न चढ़ने के पीछे राज्यों के हित निहित हैं। वे इसके लिये राजी नहीं हैं।

सरकार यह क्यों नहीं सोचती कि जब कम लागत में स्थानीय स्तर पर जन सहयोग से जोहड़ और तालाब बनाकर समाज की पानी की जरूरत पूरी की जा सकती हैं तो फिर बड़े बाँध और नदी जोड़ परियोजनाओं की क्या जरूरत है। देश में ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जहाँ समाज ने पारम्परिक ज्ञान को अपनाकर अपनी समृद्धि वापस लाने में कामयाबी पाई। जरूरी है कि समाज पानी के व्यापार और कुदरत के साथ खिलवाड़ की साजिश को समझे, तभी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा सम्भव है। ❑❑

जीवनदायिनी यमुना मृत अवस्था की ओर

यमुना भी गंगा की तरह हिमालय की गोद से निकलती है। हिमाच्छादित पर्वत बंदरपुच्छ से आठ मील उत्तर पश्चिम में कलिंद पर्वत है। इसी पर्वत की कोख से जन्मने के कारण यमुना कालिंदी भी कहलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य यमुना मईया के पिता और मृत्यु के देवता यम यमुना के भाई कहे जाते है और कृष्ण भगवान का संबंध तो यमुना के साथ जन्म से ही जुड़ गया था। कृष्ण बृज संस्कृति के जनक कहे जाते है तो वहीं यमुना जननी मानी जाती है। इसीलिए बृज में इसे 'यमुना मैया' भी कहा जाता है।

यमुना की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और दिल्ली के क्षेत्र में यमुना करीब 50 किलोमीटर बहती है। हिमालय के पहाड़ों के बीच से गुजरती और मैदानी क्षेत्र से होती हुई हरियाणा के सटे हुए गांव पल्ला से दिल्ली में इसका आगमन होता है। दिल्ली में विचरण करती यमुना दक्षिण में जैतपुर गांव के पास से ही फिर हरियाणा में चली जाती है। सदियों से ही यमुना दिल्ली की धड़कन रही है। मुगलों ने भी यमुना की उपयोगिता को माना था और इससे छेड़छाड़ नहीं की। अंग्रेजों ने भी इसकी उपयोगिता को स्वीकारा और इसमें से गंगा की तरह कोई नहर नहीं काटी। इसके मूलस्वरूप से भी कोई छेड़छाड़ न होने की वजह से ही यमुना दिल्ली की धड़कन बनी रही।

यमुना नदी पुरानी दिल्ली के लोगों की दिनचर्या में शामिल रही थी। लोग सुबह–सुबह इसके तट पर आते थे स्नान, ध्यान कर सूर्य को अर्ध्य देकर अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। नदी में जो जीव–जंतु और मछलियाँ होते हैं वह सब इसमें थे और यह सिलसिला पिछली सदी के 8वें दशक तक बना रहा। बाद में धीरे–धीरे सब खत्म होने लगा। यमुना में गंदगी और बाहर से आए लोगों की भीड़ दिल्ली में बढ़ने लगी। प्रशासन की ठोस योजना की कमी और खराब सीवर सिस्टम की वजह से इसका स्वरूप बदलने लगा। यह चिंता चांदनी चौक

सदियों से ही यमुना दिल्ली की धड़कन रही है। मुगलों ने भी यमुना की उपयोगिता को माना था और इससे छेड़छाड़ नहीं की। अंग्रेजों ने भी इसकी उपयोगिता को स्वीकारा और इसमें से गंगा की तरह कोई नहर नहीं काटी।

– सुन्दर बैसोया

में रहने वाले प्रोफेसर द्विजेन्द्र कालिया और कुछ जानकारों ने 70 के दशक में ही जता दी थी। लेकिन कोई भी कदम प्रशासन द्वारा न उठाये जाने की वजह से आज स्थिति यह है कि यमुना में स्नान करना तो दूर की बात है धार्मिक रिवाज के अनुसार पानी में आचमन भी नहीं किया जा सकता।

वजीराबाद बैराज के पहले तो नदी थोड़ी साफ भी नजर आती है लेकिन उसके बाद ओखला तक जो करीब 22 किलोमीटर का रास्ता तय करती है वह बहुत ही नारकीय है। यमुना में 18 छोटे बड़े ऐसे नाले है जो सीधे गिरते हैं, जिसमें से नजफगढ़ नाला सबसे बड़ा है। पहले एक साहबी नदी होती थी उसका पानी एक नहर के द्वारा यमुना में जाता था। 1978 में दिल्ली में बाढ़ आई थी जिसके कारण हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर स्थित ढांसा गांव में बांध का निर्माण किया गया था। जिसकी वजह से साहबी नदी सूख गई थी। आस–पास सीवर का पानी नालों के माध्यम से उस नहर में डाला जाने लगा जो यमुना को जाती थी। वही आज का नजफगढ़ नाला बन गया है।

आज यमुना में 64 प्रतिशत गंदगी इसी नाले के द्वारा यमुना में जाती है। सभी नाले वजीराबाद बैराज के बाद गिरते हैं इसीलिए वजीराबाद से ओखला तक का जो नदी का हिस्सा है वह नदी न होकर एक काले पानी की धारा नजर आती है। बरसात के दिनों को छोड़ दिया जाये तो यह स्थिति पूरे वर्ष रहती है।

नालों से आने वाला सीवर का गंदा पानी, कचरा, प्लास्टिक, फैक्ट्रियों के कैमिकल, औद्योगिक गंदगी से नदी में बहुत प्रदूषण बढ़ गया है और इसका आलम यह है कि बॉयो ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) इसमें न के बराबर है। यानि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा गायब है। जिससे मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती, और तो और गंदे पानी में रहने वाले कीडे भी मुश्किल से जिंदा रहते है। आज इसके पानी में बहुत ही बदबू आती है।

जल में गिरता जहर

- **दिल्ली में रोजाना आठ हजार मीट्रिक टन कचरा घरेलू और ओद्योगिक इकाइयों से निकलता है।**
- **यमुना में प्रतिदिन 3296 मिलियन लीटर दूषित कचरा 18 छोटे–बड़े नालों से गिरता है।**
- **23 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, जिनकी क्षमता 512 एमजीडी की है। इसके अलावा 15 औद्योगिक क्षेत्रों में 13 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं।**
- **1200 औद्योगिक इकाइयों ने दिल्ली सरकार को आश्वस्त किया है कि वे उत्सर्जित दूषित पानी को शोधित करने के लिए प्लांट लगाए हुए हैं।**

नदी में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक, पूजा सामग्री आदि कचरा डालना कानूनन अपराध है। लेकिन उसमें पड़ने वाला प्लास्टिक व अन्य कचरा कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। एक बड़ा खतरा ई–कचरा भी है। जिसका जीता जागता नजारा सीमा पुरी इलाके में देखा जा सकता है। जहाँ खराब कम्प्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाईल, टी.वी. स्क्रीन आदि की वजह से रेडिएशन फैलने का खतरा भी बना रहता है।

यमुना एक्शन प्लान

- **1993 में 15 शहरों के लिए यमुना एक्शन प्लान तैयार हुआ। जापान सरकार ने वर्ष 2010 में 700 करोड़ रूपये दिए।**
- **अन्य 6 शहरों में एक्शन प्लान केंद्र और राज्य सरकार की मदद से लागू की गई।**
- **सफाई के नाम पर पांच हजार करोड़ रूपये पानी में बहा दिए गए।** ❑

यमुना के किनारे सरकार की सहमति से भी वहां बहुत निर्माण हुआ है जबकि किसी भी नदी के किनारे निर्माणों पर पाबंदी है और भू–माफियों ने काफी अतिक्रमण भी किया है। नैशनल ग्रीन ट्रिबुनल बनने के बाद कुछ लगाम जरूर लगी है। लेकिन वह भी कहां तक कामयाब होगी देखना बाकी है। वैसे सवाल इस ट्रिबुनल पर भी उठता रहा है। हाल में 11 से 13 मार्च 2016 को श्री–श्री रविशंकर के कार्यक्रम के लिए पांच करोड़ का जुर्माना लगाया गया जबकि उनकी सरं था आर्ट ऑफ लिविगं के डायरेक्टर गौतम विग ने बताया कि कार्यक्रम से पहले भी हमने यमुना की सफाई की और 2010 में भी 'मेरी दिल्ली मेरी यमुना' कार्यक्रम के तहत श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व में 512 टन कचरा हम लोगों ने यमुना से साफ किया था।

कितना पानी गंदा और कहां–कहां से हो रहा है और आज तक हजारों करोड़ रूपया यमुना सफाई पर लगा दिया गया है। दो एक्शन प्लान बने। इन आंकडों के जाल में न फंसे तो भी इसकी स्थिति बडी ही दयनीय है। यह स्थिति बनाने में सरकारों के साथ–साथ दिल्ली वालों का भी पूरा सहयोग रहा है। दिल्ली यमुना से केवल पांच प्रतिशत पानी लेती है और 79 प्रतिशत इसमें गंदगी देती है। ऐसा नहीं है कि यमुना को केवल गंदा करने वाले ही है। इसे साफ रखने के लिए कुछ–कुछ प्रयास व्यक्तिगत, सामाजिक–धार्मिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से भी होते रहते हैं। लेकिन यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होते हैं।

अभी हाल में भारत सरकार में

की है। यमुना को साफ रखने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले, जो इसमें नालों के द्वारा गंदगी डाली जाती है उसे बंद किया जाये। उसके लिए वजीराबाद से ओखला तक यमुना के दोनों ओर कंकरीट के

केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि हम यमुना को साफ करके लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक छोड़ने के लिए इसमें बोट चलायेंगे और इसे पिकनिक स्पॉट बनायेंगे। एक अन्य केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से इसकी सफाई के लिए मुलाकात कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने पहल करके यमुना आरती भी शुरू

चैनल बनाये जायें। यदि अभी यह संभव न हो तो नालों के मुहानों पर ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे में सोचना चाहिये जिससे पानी साफ होकर नदी में जाये। साथ ही नदी को तीन से चार मीटर तक और गहरा किया जाये। जिससे पानी उसमें बना रहेगा व पानी जमीन के अंदर भी चला जायेगा।

यमुना में हमेशा पानी का बहाव बनाये रखने के लिए पड़ोसी राज्यों से तालमेल बनाये रखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात नदी को पुराने स्वरूप में लाने के लिए सरकार को जनता का सहयोग लेना चाहिए। क्योंकि जनभागीदारी से ही यमुना की सफाई की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी। दिल्ली वालों को भी यह शपथ लेकर करना होगा। वह ऐसा कोई कार्य न करे और गंदगी न डालें जिससे यमुना गंदी हो। अगर हम इतना कर सके तो एक दम तोड़ती नदी को जीवन मिल सकता है। जल है तो कल है, नहीं तो बोट चलाने की बात जो कही गई है, बोट चलाना तो दूर कोई कीड़ा भी नदी में जीवित नहीं चल पाएगा। सरकार की नीयत और लोगों की इच्छाशक्ति ही इस मरती नदी को बचा सकती है।

रहिम ने भी कहा है–

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून।

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

विजय माल्या

कानून को छकाने की कोशिश

भारत का कानून विजय माल्या का इंतजार कर रहा है। परर्वतन निदेशालय सीबीआई और आयकर विभाग के साथ तमाम न्यायिक इकाइयों को माल्या की ओर से किसी सकारात्मक पहल की उम्मीद तो हैं, पर कोई नहीं जानता कि माल्या कब अपनी खामोशी तोड़ेगे और कानून का सामना करेंगे। अभी उन्होंने मई तक का समय प्रवर्तन निदेशालय से मांगा है। वैसे माल्या कानून को घुमाना खूब जानते हैं। बंद होते कारोबार में अरबों का बैंक लोन लेने की कला माल्या के अलावा किसके पास है। वो भी बिना किसी उपयुक्त रेहन योग्य परिसंपत्ति के।

आज सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय इसी बात का रोना रो रहे हैं कि आखिर बैंकों ने बिना योग्य कोलेटेरल के लोन कैसे दे दिया। खासकर आईडीबीआई द्वारा 900 करोड़ के लोन सबको आश्चर्य में डाल रहा है। यह लोन माल्या ने तब लिया था जब सारे बैंकों ने किंगफिशर को और पैसे देने से मना कर दिया था और साथ ही आरबीआई को भी माल्या के डिफाल्टर होने की सूचना दे दी थी। माल्या मजे करने के लिए लोन ले रहे थे कि डूबते कारोबार को बचाने के लिए आखिरी जतन कर रहे थे या फिर सचमुंच पैसे को पार कराने में लगे थे। इन सभी सवालों का जवाब निष्पक्ष और त्वरित जांच में है।

आज सबसे बड़ा सवाल है कि माल्या के पास उचित कोलेटेरेल नहीं होने के बावजूद किंगफिशर को लोन कैसे मिला? इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिस ब्रांड के आधार पर बैंकों ने बिना उचित रेहन संपत्ति के लोन दे दिया था आज उसकी न तो कोई कीमत है और न उसे बेचने का कानूनी आधार। मुश्किल से लोग यह समझ पायेंगे कि लगातार घाटा उठाने के बावजूद माल्या किंगफिशर एयर लाइंस में क्यों पैसा फूंकते जा रहे थे। वह इस बात की होर में क्यों लगे रहे कि किंगफिशर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयर

आज सीबीआई और प्रर्वतन निदेशालय इसी बात का रोना रो रहे हैं कि आखिर बैंकों ने बिना योग्य कोलेटेरल के लोन कैसे दे दिया। खासकर आईडीबीआई द्वारा 900 करोड़ के लोन सबको आश्चर्य में डाल रहा है।

– **विक्रम उपाध्याय**

लाइंस का तमगा हासिल कर ले। दरअसल उदारीकरण के बाद बिजनेस के ब्रांड वैल्यू का अपना महत्व अलग से बनने लगा थ और बढ़ने भी लगा था। बड़े बड़े ब्रांड मैनेजर पूरी दुनिया में छा जाने लगे और ब्रांड वैल्यूअर ब्रांड की कीमत भी लगाने लगे।

अपने इस एयरलाइंस को टॉप का ब्रांड बनाने के लिए माल्या ने इसे लाइफस्टाइल से जोड़ कर पेश किया। दुनिया के तमाम अफसराओं और मॉडलों को अपने साथ जोड़ने के साथ साथ उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी बखूबी इस्तेमाल किया। मंगल पांडे फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग कराने के साथ इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार को मुफ्त हवाई यात्रा और अन्य सुविधाओं से नवाजने में माल्या ने कोई कसर नहीं छोड़ी। माल्या ने जितना संभव हो सका अपने एयरलाइंस के बिजनेस को चकाचौंध की दुनिया से जोड़ दिया और इसका भरपूर फायदा भी उठाया।

जब माल्या के पास संपत्ति रेहन रखने को काम पड़ने लगी तब उसने अपने ब्रांड वैल्यू का दाव खेला और एक समय इसकी कीमत 4100 करोड़ रुपये आंकी गई। किंगफिशर एयरलाइंस की ब्रांड वैल्यू का आकलन 2011–12 में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ग्रांट थॉरटन ने किया था। इस ग्रांट थॉरटन के ग्राहकों में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, लॉयड बैंक, मेसा एयर ग्रुप और और सनबेल्ट स्टील टेक्सास जैसे बड़े बिजनेस ब्रांड हैं। अब समझा जा सकता है कि आखिर भारतीय बैकों ने क्योंकर माल्या को ब्रांड वैल्यू के आधार पर लोन दिया। आज माल्या के इस किंगफिशर एयराइंस के ब्रंाड को कोई पूछने वाला नहीं। माल्या की पहचान यूबी ग्रुप ने ही हाल में किंगफिश एयरलाइसं के ब्रांड को खरीदने से इनकार कर दिया है। अब माल्या ब्रिवरेज डिवीजन में अपनी हिस्सेदारी विदेशी कंपनी डियागों को बेच चुके हैं।

जब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर माल्या को देश से भगाने का आरोप लगाया तो भाजपा ने कांग्रेस से ही प्रश्न कर दिया कि आखिर माल्या को लोन दिलाने में किसने सहयोग किया। लोन के लिए अहर्ता नहीं होने के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिये बैंकों को माल्या को पेसे देने पर क्यों मजबूर किया गया? अब इस बात का किसी के पास सबूत नहीं किया किसने किस पर माल्या के लिए दबाव डाला। पर अब उस समय की परिस्थितियों और घटनाओं के आधार यह कहा जा रहा है कि सभी लोन में भले ही नहीं लेकिन आईडीबीआई के लोन में माल्या को परदे के पीछे से सहयोग किया गया और ईडी की जांच भी उसी दिशा में हो रही है। ईडी आईडीबीआई के बड़े प्रबंधकों से कई बार पूछ ताछ कर चुका है। ईडी को आशंका है कि आईडबीआई द्वारा जारी लोन के बड़े हिस्से को ही देश के बाहर भेजा गया।

जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आईडीबीआई ने लोन की स्वीक ति से पहले मना कर दिया था। उसके कई प्रबंधकों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 900 करोड़ रुपये के लोन के लिए माल्या क्वालीफाई नहीं करते, न तो उनके पास पर्याप्त कोलेटेरेल है और ना वह अन्य मानदंडों पर खरा उतरते हैं। उन्होंने सरकार को कई प्रकार करों और शुल्कों का भुगतान नहीं किया और न वे अपने अंतरराष्ट्रीय देनदारों को ही संतुष्ट कर सके हैं। लेकिन अचानक लोन न सिर्फ स्वीक त कर लिया गया बल्कि तीन हफ्ते के भीतर ही लोन देने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई। कहते हैं कि सरकार में शामिल किसी रसूख वाले सख्शियत ने माल्य और तब के आईडीबीआई के सीएडी योगेश अग्रवाल के बीच मिटिंग कराई और इन दिनों के बीच हुई कुछ मुलाकातों के बाद ही आईडीबीआई ने 900 करोड़ रुपये जारी कर दिए। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में इन दोनों के बीच मुलाकात का जिक्र किया है।

कई अन्य सवालों के साथ एक और सवाल लोगों को मथ रहा है कि आखिर माल्या बैंकों के 9000 करोड़ रुपये चुकायेंगे कहां से और उनके पास चुकाने के लिए है क्या? इसी सवाल के साथ एक सवाल और भी जुड़ा है कि माल्या वापस भारत आएंगे भी या नहीं? अन्य सवालों की तरह ये सवाल भी अनुतरित ही लग रहे हैं। एक तो माल्या सीधे किसी के संपर्क में नहीं है और न उनकी तरफ से कोई सीधा जवाब किसी को मिल रहा है। छन छन कर या ईधर उधर से जो खबरे आ रही हैं उनसे कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। माल्या की ओर से ईडी को एक जवाब जरूर मिला हे जिसमें कहा गया है कि वह 17 मार्च को ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सकते वे भारत अप्रैल में ही आ सकते हैं। इसके अलावा कहने या बताने को कुछ भी नहीं है।

हालांकि सरकार और खासकर वित्तमंत्री अरुण जेटली यह दावा कर रहे हैं कि विजय माल्या से पाई पाई वसूली जाएगी, पर कब और कैसे इसका भी जवाब नहीं है। ईडी और सीबीआई साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। ईडी यह जानकारी जुटाने में लगा है कि माल्या ने 9000 करोड़ के लोन में से कितना और कब भारत के बाहर भेजने में कामयाब हो सके हैं तो सीबीआई इस जांच में लगी है कि लोन लेने के लिए माल्या ने किस तरह दस्तावेजों ओर नियम कायदों में फरेब किया। ईडी ने लोने देने वाले सभी बैंकों को पत्र लिखकर लोन से सबंधित सभी जानकारी व दस्तावेज देने को कहा है तो सीबीआई किंगफिशर एयरलाइंस के पुराने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछ ताछ में लगा है। ❑❑

उद्योगों जैसा हो कृषि राहत पैकेज

जनवरी और फिर फरवरी की शुरूआत में अचानक तापमान में बढ़ोत्तरी, फिर बेमौसम बारिश, तेज हवाएं और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत नौ राज्यों के किसान एक बार फिर मौसम की मार झेल रहे हैं। किसी भी किसान के लिए अपनी लगभग पकी हुई फसलों को जमीन पर गिरी देखने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। 2013 के रबी सीजन की शुरूआत से अब तक लगातार चौथे साल देश के मध्य एवं उत्तरी के किसानों को सर्दियों के महीने में असामान्य मौसमी पैटर्न की मार पड़ी है।

2014 और 2015 में लगातार दो साल के सूखे ने भी किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के उस असंवेदनशील बयान की याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'असाधारण बरसात तथा ओलावृष्टि तो होती रहेगी और घाटा सहन करने के लिए किसानों को सुदृढ़ बनना होगा।' हालांकि, ऐसी सलाह उन्होंने शुगर इंडस्ट्री के लिए कभी नहीं दी, जिसके लिए वह हमेशा कटोरा लेकर सरकार से ज्यादा अनुदान की मांग करते रहते थे।

बहरहाल, खेतं में खड़ी गेहूं, सरसों, चना और धनिया की फसलों के नुकसान का आकलन अभी किया जाना है, पर शुरूआती रिपोटर्स 5–10 फीसदी के नुकसान का संकेत कर रही हैं। अगर मौसमी मार से प्रभावित इलाकों में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज हवां का प्रकोप दोबारा नहीं होता, तो फसल का नुकसान कम ही होगा। पिछले साल बेमौसम बरसात का प्रकोप अभूतपूर्व था और अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सौ साल का रिकॉर्ड टूट गया, जिसके कारण सैकड़ों किसान आत्महत्या करने लगे और बहुत से किसान तो फसलों के नुकसान को देखकर हार्टअटैक का शिकार बन गए। पिछले साल हुई

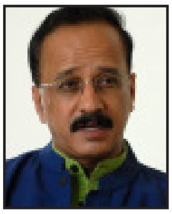

किसी भी किसान के लिए अपनी लगभग पकी हुई फसलों को जमीन पर गिरी देखने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। 2013 के रबी सीजन की शुरूआत से अब तक लगातार चौथे साल देश के मध्य एवं उत्तरी के किसानों को सर्दियों के महीने में असामान्य मौसमी पैटर्न की मार पड़ी है।

– देविंदर शर्मा

फसल की भारी हानि से गेहूं उत्पादन अनुमानित 957.6 लाख टन की अपेक्षा घटकर 865.3 लाख टन रह गया। सिर्फ एक महीने पहले ही कृषि मंत्रालय ने 2016 में 938.2 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया था। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही जमीनी हकीकत का पता चलेगा, तो इस आंकड़े में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ असामान्य बरसात और ओलावृष्टि से ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इस रबी सत्र में असाधारण रूप से गर्म और शुष्क सर्दियों ने भी अपना प्रकोप दिखाया है। खेतों में गिरी और पानी में डूबी हुई फसलें, बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से हुई तबाही के जीवंत प्रमाण हैं। इस साल सर्दी में होने वाली रोपाई में भी कमी आई है। अकेले तेलंगाना में बोये गए क्षेत्र में छह लाख हेक्टेयर की गिरावट हुई है। कुल मिलाकर देखें, तो इस साल रबी सत्र में बोये गए क्षेत्र में तीन लाख हेक्टेयर की कमी आई है। इस बीच, खड़ी फसलों के नुकसान का अग्रिम आकलन करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक ने चालू रबी सत्र में 70 प्रतिशत फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार से 1,417 करोड़ रूपये की मांग की है। कर्नाटक में 24.64 लाख हेक्टेयर रकबे में फसलें प्रभावित हुई हैं। पिछले साल अगस्त महीने में खरीफ सत्र में राज्य के 37 में से 27 जिलों में पड़े सूखे की कर्नाटक सरकार की घोषणा के बाद पड़ी मौसमी मार के असर को समझा जा सकता है। दिसंबर 2015 तक 10 अन्य राज्य भी सूखे की घोषणा कर चुके थे।

हालांकि, कृषि मंत्रालय ने प्रभावित किसानों को वित्तीय मदद का भरोसा दिलाया और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से हर तरह की मदद का वायदा किया।

सरकार वित्तीय पैकेज देकर निर्यात क्षेत्र को संकट से उबार सकती है और औद्योगिक उत्पादन बनाए रखने के लिए उद्योगों को राहत भी दे रही है।

मौसम की मार से लगातार जिस तरह फसलों के नुकसान की पुनरावृत्ति हो रही है और जिस ढंग से इससे निपटा जा रहा है, उससे जाहिर होता है कि इस चुनौती को किस तरह हल्के में लिया जा रहा है। फसल नष्ट होने या फिर कम उत्पादन होने से न केवल कृषि के लिए संकट खड़ा हो जाता है, बल्कि इसके कारण किसान कर्ज में डूब जाते हैं और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में खाद्यान्न उत्पादन में होने वाली कमी से कैरीओवर स्टॉक पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए आवश्यक है। इस साल केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 168 लाख टन है, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम है। ऐसे में गेहूं के आयात की बढ़ती हुई मांग को देखकर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। कई न्यूज एजेंसियां लगातार दूसरे साल घरेलू उत्पादन में गिरावट को देखते हुए बड़े पैमाने पर गेहूं के आयात की भविष्यवाणी कर रही हैं। फिलहाल त्वरित आपदा राहत निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम होगा। नुकसान के आकलन और राहत वितरण में तेजी की जरूरत है।

कई वर्षों से जिस तरह किसानों पर मार पड़ी है और जिस तरह सोच–समझकर फसलों के कम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, उसने कृषि संकट को बढ़ावा दिया है। अगर सरकार वित्तीय पैकेज देकर निर्यात क्षेत्र को संकट से उबार सकती है और औद्योगिक उत्पादन बनाए रखने के लिए उद्योगों को जैसे राहत दी जा रही है, ऐसे में यह हैरान करता है कि कृषि क्षेत्र ही इस तरह की आर्थिक राहत पैकेज से अछूता क्यों है। किसानों को कम से कम तीन लाख करोड़ रूपये का राहत पैकेज दिए जाने की जरूरत है। यह बहुत हद तक 2008–09 में वैश्विक मंदी के दौरान घरेलू उद्योगों को दी गई राहत की तरह ही मानी जानी चाहिए। कई अर्थशास्त्री तर्क दे रहे हैं कि जितना बड़ा खाद्यान्न भंडार होगा, उतना अधिक सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। संकेत साफ है कि सरकार को महज लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही खाद्यान्नों की खरीद करनी चाहिए। यह एक दोषपूर्ण नीतिगत निर्णय है और इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। अंततः कृषि शोधों में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि बदलते मौसमी पैटर्न की मार से होने वाले नुकसान से आखिर कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित युवाओं का एक कैडर भी तैयार किया जा सकता है, जो फसल के नुकसान का आकलन करने में मदद कर सकता है। ❑❑

लेखक कृषि–व्यापार एवं नीति विशेषज्ञ हैं।

स्वदेशी अपनाओ - देश समद्ध बनाओ

वस्तु	स्वदेशी उत्पादन-प्रयोग करें
नहाने का साबुन	गोदरेज, संतूर, निरमा, स्वस्तिक, मैसूर सँडल, विप्रो–शिकाकाई, फ्रेश, अफगाण, कुटीर, होमाकोल, प्रिमियम, मीरा, मेडिमिक्स, पितांबरी, विमल, चंद्रिका, गंगा, सिंथाल, वनश्री, सर्वोदय, नीमा, अनुरा, तथा लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
कपड़े धोने का साबुन	स्वस्तिक, ससा, प्लस, निरमा, ॲक्टो, विमल, हीपोलीन, डेट, पितांबरी, बी.बी., फेना, उजाला, ईज़ी, घड़ी, जेंटिल, मंजुला, अनुरा, अन्य स्थानिक उत्पादन, अन्य लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	टिप्स एण्ड टोज, श्रंगार, सिंथॉल, संतूर, इमामी, अफगाण, बोरोप्लस, तुलसी, वीको टर्मरिक, अर्निका, हेयर एण्ड केयर, हिमानी, पॅराशूट, डॅन्ड्रफ सोल्युशन, हिमताज, सिल्केशा, नाईल, फेम, बलसारा, जेके, डाबर झंडू, सांडू, बेद्यनाथ, हिमालय, भास्कर, तन्वी, बोरोलीन, केराफेड, बजाज सेवाश्रम, प्रकाश, कोकोराज, प्रिमियम, मूव, क्रैक क्रीम, आयुर, पार्क एवेन्यू, कासवछाप नेचर इसेस और लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	बबूल, प्रॉमिस, विको, ओरा, अमर, अँकर, डाबर, बंदर छाप, टु जेल, चॉईस, मिसवाक, अजय, हर्बोडेंट, अजंता, गरवारे ब्रश, क्लासिक, ईगल, दंतपोला, बंदर छाप, वैद्यनाथ, युवराज, इमामी तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	गॉदरेज, अफगाण, इमामी, सुपर, स्वदेशी, सुपरमैक्स, अशोक, वी–जॉन, टोपाज, पनाना, प्रीमियम, पार्क एवेन्यू, लेझर, विद्युत, जे.के. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	साठे, बेकमेन, मोनॅको, क्रेकजैक, गिट्स, शालीमार, पैरी, रावलगांव, निलगिरी, क्लासिक, अमूल, न्यूट्रामूल, मॉन्जीनीज, आरे, कॅमको, सम्राट, रॉयल, विजया, इंडाना, सफल, एशियन, विल्स ब्रेड, वेरका, सागर, सपन, प्रिया गोल्ड, न्यूट्रीन, शांग्रिला, चॅम्पियन, ॲम्प्रो, पार्ले, तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
चाय कॉफी	गिरनार, हसमुख, टाटा टी, आसाम टी, सोसायटी, सपट (इस्टंट), डंकन, बह्मपुत्र, एम.आर., शन, टिपस, इंडीया, अशोक, तेज, टाटा कॅफे, कन्सोलिडेटेट कॅफे, टाटा–टेटली और अन्य स्थानीय उत्पादन
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	एनर्जी, सोसयो, कॅम्पाकोला, गुरूजी, ओन्जुस, जाम्पिन, नीरो, पिंगो, फ्रूटी, आस्वाद, डाबर, माला, रॉजर्स, रसना, हमदर्द, मैप्रो, रेनबो, कॅल्वर्ट, सीटेम्ब्लिका, रूह–आफजा, जय गजानन, हल्दीराम, गोकुल, बीकानेर, वेकफील्ड, नोगा, प्रिया, अशोक, मदर्स रेसेपी, उमा, एच.पी.एम.सी उत्पाद, हिम तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
पीने का पानी	बिसलेरी, बैली, नॅचरल, अन्य स्थानीय उत्पादन
आईस्क्रीम	दिनशॉ, जॉय, वाडीलाल, श्रीराम, पेस्तनजी, नेचर वर्ल्ड, गोकूल, अमूल, हिमालय, निरूला, पेरीना, मदर डेयरी, आरे, विंडी, हॅव मोर, वेरका तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	सनफ्लावर, मारूति, पोस्टमैन, धारा, रॉकेट, गिन्नी, स्वीकार, कॉरनेला, सनड्राप, रथ, मोहन, उमंग, विजया, सपन, पॅराशूट, अशोक, सफोला, कोहिनूर, मधुर, इंजन, गगन, अमत, वनस्पति, रामदेव, एमडीएच, एवरेस्ट, बेडेकर, कुबल, डाबर, सहकार, लिज्जत, गणेश, शक्तिभोग आटा, टाटा नमक, एम.टी.आर. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
विद्युत उपकरण गहोपयोगी वस्तु	विडियोकॉन, बी.पी.एल, ओनिडा, सलोरा, ईटीएण्डटी, टी–सीरीज, नेल्को, वेस्टर्न, अपट्रॉन, केल्ट्रान, कॉस्मिक, टीवीएस, गोदरेज, क्राउन, बजाज, उषा, पोलर, एँकर, सूर्या, ओरिएन्ट, सिन्नी, टूल्लू, क्रॉम्पटन, रवी, जय शंकर, कैलाश, श्रीराम, लायड्स, ब्लू स्टार, व्होल्टास, कूल होम, खेतान, एव्हरेडी, जीप, नोविनो, ॲम्प्रो, निर्लेप, इलाईट, अंजली, जयको, सुमीत, बंगाल, मैसूर, हॉकिन्स, प्रेस्टीज, महाराजा, जयपान, प्रेशर कुकर तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
घड़ियां	टाइटन, अजन्ता, एचएमटी, मैक्सिमा, आल्विन,
लेखन सामग्री	ज़ीफ्लो, विल्सन, कैम्लिन, रेव्हलॉन, रोटोमॅक, सेलो, स्टिक, चंद्रा, मोंटेक्स, कैमल, बिट्टू, स्टिक, प्लेटो, कोलो, त्रिवेणी, फ्लोरा, अप्सरा, नटराज, हिंदुस्तान, ओमेगा, लोटस, कैमे, लिंक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
जूते, चप्पल पॉलिश	लखानी, लिबर्टी स्टैन्डर्ड, एक्शन, पैरागॉन, फ्लॅश, करोना, वेलकम, रेक्सोना, रिलैक्सो, लोटस, रेड–टेप, फिनिक्स, वायकिंग, बिल्ली, कार्नोबा, किवी शू पॉलिश, फ्लेक्स, बुडलॅनड तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
तैयार कपड़े	पीटर इंग्लैंड, व्हॅन हुसेन, ॲलेन सॉलीए, लुई फिलिप, कलरप्लस, मफतलाल, ट्रेंड, केम्ब्रिज, डबल बुल, झोडिएक, अरविंद डेनिम, डॉन, प्रोलीन, टीटी, लक्स, अमूल, वीआईपी, रूपा, रेमण्ड, पार्क एवेन्यू, अल्टिमो, न्यूपोर्ट, किलर, फ्लाईंग मशीन, डयूक्स, कोलकाता, लुधियाना तथा तिरुपुर के सभी हौजरी सहित अन्य स्थानीय उत्पादन

जनवरी — पौष-माघ २०७२

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
३१ 31 रविवारी सप्तमी	रविपुष्यामृत योग मंत्रसिद्धि और औषधि-प्रयोग के लिए विशेष फलप्रद है। ❊ प्रतिदिन एकाग्रता के साथ गुरुदेव का मानसिक पूजन करके फिर जप-ध्यान करने से जप-ध्यान सौ गुना प्रभावशाली हो जाता है।				१ 1 पौष कृ.प. सप्तमी	२ 2 अष्टमी
३ 3 नवमी	४ 4 दशमी	५ 5 सफला एकादशी	६ 6 सफला एकादशी, द्वादशी (वृद्धि तिथि)	७ 7 द्वादशी, प्रदोष व्रत	८ 8 त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि	९ 9 चतुर्दशी/अमावस्या
१० 10 पौष शु.प. प्रतिपदा	११ 11 द्वितीया	१२ 12 तृतीया	१३ 13 विनायक चतुर्थी	१४ 14 मकर संक्रांति, पंचमी	१५ 15 मकर संक्रांति, षष्ठी	१६ 16 सप्तमी
१७ 17 अष्टमी	१८ 18 नवमी	१९ 19 दशमी	२० 20 पुत्रदा एकादशी	२१ 21 द्वादशी, प्रदोष व्रत	२२ 22 त्रयोदशी	२३ 23 चतुर्दशी/पौषी पूर्णिमा
२४ 24 माघ कृ.प. प्रति. (वृद्धि तिथि)	२५ 25 प्रतिपदा	२६ 26 द्वितीया	२७ 27 तृतीया, संकष्ट चतुर्थी	२८ 28 चतुर्थी	२९ 29 पंचमी	३० 30 षष्ठी

जनवरी : ५. गुरु गोबिंदसिंह जयंती १२. स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस १४. मकर संक्रांति १५. मकर संक्रांति (पुण्यकाल : सूर्योदय से सूर्यास्त) २२. चतुर्दशी-आर्द्रा नक्षत्र योग (सुबह ८-१४ से रात्रि ८-०१ तक) (ॐकार-जप अक्षय फलदायी) २३. माघ स्नानारम्भ, सुभाषचन्द्र बोस जयंती २४. रविपुष्यामृत योग (सूर्योदय से रात्रि ८-४६ तक) २६. गणतंत्र दिवस २८. लाला लाजपतराय जयंती ३०. महात्मा गांधी पुण्यतिथि ३१. स्वामी रामानंदाचार्य जयंती, रविवारी सप्तमी (सूर्योदय से शाम ७-४५ तक)

फरवरी — माघ-फाल्गुन २०७२

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१४ फरवरी मातृ-पितृ पूजन दिवस	१ 1 माघ कृ.प. अष्टमी	२ 2 नवमी	३ 3 दशमी	४ 4 षट्तिला एकादशी	५ 5 द्वादशी	६ 6 त्रयो., शनिप्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
७ 7 चतुर्दशी	८ 8 सोमवती अमावस्या	९ 9 माघ शु.प. प्रतिपदा	१० 10 द्वितीया	११ 11 तृतीया, विनायक चतुर्थी	१२ 12 चतुर्थी/वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा	१३ 13 षष्ठी, विष्णुपदी संक्रांति
१४ 14 रविवारी सप्तमी	१५ 15 भीष्माष्टमी	१६ 16 नवमी	१७ 17 दशमी	१८ 18 जया एकादशी	१९ 19 द्वादशी	२० 20 त्रयोदशी, शनिप्रदोष व्रत
२१ 21 चतुर्दशी	२२ 22 माघी पूर्णिमा	२३ 23 फाल्गुन कृ.प. प्रतिपदा	२४ 24 द्वितीया	२५ 25 तृतीया	२६ 26 संकष्ट चतुर्थी (वृद्धि तिथि)	२७ 27 चतुर्थी
२८ 28 पंचमी	२९ 29 षष्ठी	❊ शिशिर ऋतु : १८ फरवरी तक ❊ वसंत ऋतु : १९ फरवरी से १८ अप्रैल तक ❊ सोमवती अमावस्या, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी व रविवारी सप्तमी को किये गये जप, तप, मौन, ध्यान आदि का प्रभाव अक्षय होता है।				

फरवरी : ८. सोमवती अमावस्या (सूर्योदय से रात्रि ८-१० तक), अहमदाबाद आश्रम स्थापना दिवस १३. विष्णुपदी संक्रांति (पुण्यकाल : सुबह ८ से दोपहर २-२६ तक) १४. मातृ-पितृ पूजन दिवस, रविवारी सप्तमी (सूर्योदय से रात्रि २-१३ तक) १९. छत्रपति शिवाजी जयंती (दिनांक अनुसार) २०. गुरु गोरखनाथ जयंती २२. संत रविदास जयंती २८. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

मार्च — फाल्गुन-चैत्र २०७२

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
७ मार्च, महाशिवरात्रि 'बं' बीजमंत्र का सवा लाख जप जोड़ों के दर्द व वायुरोगों में लाभदायी है।		१ 1 फाल्गुन कृ.प. सप्तमी	२ 2 बुधवारी अष्टमी	३ 3 नवमी	४ 4 दशमी	५ 5 विजया एकादशी
६ 6 द्वादशी, प्रदोष व्रत	७ 7 त्रयोदशी, महाशिवरात्रि	८ 8 चतुर्दशी, अमावस्या	९ 9 अमा./फाल्गुन शु.प. प्रतिपदा	१० 10 द्वितीया	११ 11 तृतीया	१२ 12 विनायक चतुर्थी
१३ 13 पंचमी	१४ 14 षष्ठी, षडशीति संक्रांति	१५ 15 सप्तमी	१६ 16 बुधवारी अष्टमी	१७ 17 नवमी	१८ 18 दशमी	१९ 19 आमलकी एकादशी
२० 20 द्वादशी, प्रदोष व्रत	२१ 21 त्रयोदशी	२२ 22 चतुर्दशी, पूर्णिमा	२३ 23 होली पूर्णिमा	२४ 24 चैत्र कृ.प. प्रतिपदा, धुलेंडी	२५ 25 द्वितीया	२६ 26 तृतीया
२७ 27 संकष्ट चतुर्थी	२८ 28 पंचमी	२९ 29 षष्ठी (वृद्धि तिथि)	३० 30 षष्ठी	३१ 31 सप्तमी	महाशिवरात्रि को रात्रि-जागरण व 'ॐ... नमः... शिवाय...' ऐसे प्लुत उच्चारण से आत्मविश्रांति मिलती है।	

मार्च : २. बुधवारी अष्टमी (सूर्योदय से शाम ५-२१ तक) ३. समर्थ रामदास नवमी ७. महाशिवरात्रि व्रत, रात्रि-जागरण, शिव-पूजन (निशीथकाल : रात्रि १२-२५ से १-१४), (प्रहर :- प्रथम : शाम ६-४५ से, द्वितीय : रात्रि ९-४७ से, तृतीय : मध्यरात्रि १२-५० से, चतुर्थ : ८ मार्च प्रातः ३-५२ से) ८. द्वापर युगादि तिथि, विश्व महिला दिवस ९. खग्रास सूर्यग्रहण (भूभाग में ग्रहण समय : प्रातः ४-४९ से सुबह १०-०४) (भारत का पश्चिम भाग छोड़कर अन्य भागों में दिखेगा। जहाँ दिखेगा वहाँ नियम पालनीय हैं।) १४. षडशीति संक्रांति (पुण्यकाल : सुबह ११-१८ से शाम ५-४३) १६. बुधवारी अष्टमी (सूर्योदय से सुबह १०-०६) २३. होलिका दहन, श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती, मांद्य चन्द्रग्रहण (भारत में दिखेगा, नियम पालनीय नहीं हैं) २४. धुलेंडी २५. संत तुकाराम द्वितीया, गुड फ्राइडे २६. छत्रपति शिवाजी जयंती (तिथि अनुसार) २९. संत एकनाथ षष्ठी

अप्रैल — चैत्र-वैशाख २०७२-७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१८ अप्रैल : पूज्य संत श्री आशारामजी बापू का ७६वाँ अवतरण दिवस ग्रीष्म ऋतु : १९ अप्रैल से १९ जून तक गुरुपुष्यामृत योग सर्वसिद्धिकर है। विवाह छोड़कर अन्य मांगलिक कार्यों के लिए यह महाफलदायी है।					१ 1 चैत्र कृ.प. अष्टमी	२ 2 नवमी
३ 3 दशमी/पापमोचनी एकादशी	४ 4 पापमोचनी एका., द्वादशी	५ 5 त्रयो., प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि	६ 6 चतुर्दशी	७ 7 अमावस्या	८ 8 चैत्र शु.प. प्रति., चेटीचंड	९ 9 द्वितीया/तृतीया
१० 10 विनायक चतुर्थी	११ 11 पंचमी	१२ 12 स्कंद षष्ठी	१३ 13 सप्तमी, मेष संक्रांति	१४ 14 दुर्गाष्टमी	१५ 15 श्रीराम नवमी	१६ 16 दशमी
१७ 17 कामदा एकादशी	१८ 18 द्वादशी	१९ 19 अनंग त्रयोदशी	२० 20 चतुर्दशी (वृद्धि तिथि)	२१ 21 चतुर्दशी, पूर्णिमा	२२ 22 चैत्री पूर्णिमा	२३ 23 वैशाख कृ.प. प्रतिपदा
२४ 24 द्वितीया	२५ 25 तृतीया, संकष्ट चतुर्थी	२६ 26 मंगलवारी चतुर्थी	२७ 27 पंचमी	२८ 28 षष्ठी	२९ 29 सप्तमी	३० 30 अष्टमी

अप्रैल : ३. साँईं श्री लीलाशाहजी महाराज प्राकट्य दिवस ८. चैत्री नूतन वर्ष वि.सं. २०७३ प्रारम्भ, गुड़ी पड़वा (पूरा दिन शुभ मुहूर्त), चैत्री नवरात्र प्रारम्भ, चेटीचंड ९. मत्स्य जयंती १३. मेष संक्रांति (पुण्यकाल : दोपहर १२-३१ से सूर्यास्त तक) १४. दुर्गाष्टमी, गुरुपुष्यामृत योग (दोपहर २-३६ से १५ अप्रैल सूर्योदय तक), डॉ. आंबेडकर जयंती १५. श्रीराम नवमी २०. महावीर स्वामी जयंती २२. श्री हनुमान जयंती, वैशाख स्नानारम्भ, छत्रपति शिवाजी पुण्यतिथि, उज्जैन कुम्भ का प्रथम शाही स्नान २६. मंगलवारी चतुर्थी (सूर्योदय से शाम ७-१२ तक) २८. पूज्य संत श्री आशारामजी बापू का ७६वाँ अवतरण दिवस

मई — वैशाख-ज्येष्ठ २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१ 1 वैशाख कृ.प. नवमी	२ 2 दशमी	३ 3 वरूथिनी एकादशी	४ 4 द्वादशी, प्रदोष व्रत	५ 5 त्रयोदशी/चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि	६ 6 अमावस्या	७ 7 वैशाख शु.प. प्रतिपदा
८ 8 द्वितीया	९ 9 अक्षय तृतीया	१० 10 विनायक चतुर्थी, मंगलवारी चतुर्थी	११ 11 पंचमी	१२ 12 षष्ठी, गंगा सप्तमी	१३ 13 सप्तमी	१४ 14 अष्टमी, सीता नवमी, विष्णुपदी संक्रांति
१५ 15 नवमी	१६ 16 दशमी	१७ 17 मोहिनी एकादशी	१८ 18 द्वादशी	१९ 19 त्रयोदशी, प्रदोष व्रत	२० 20 चतुर्दशी	२१ 21 वैशाखी/बुद्ध पूर्णिमा
२२ 22 ज्येष्ठ कृ.प. प्रतिपदा	२३ 23 द्वितीया	२४ 24 तृतीया (वृद्धि तिथि)	२५ 25 तृतीया, संकष्ट चतुर्थी	२६ 26 चतुर्थी	२७ 27 पंचमी	२८ 28 षष्ठी
२९ 29 रविवारी सप्तमी/अष्टमी	३० 30 नवमी	३१ 31 दशमी	विष्णुपदी संक्रांति में किये गये जप-ध्यान व पुण्यकर्म का फल लाख गुना होता है। (पद्म पुराण) षडशीति संक्रांति में किये गये जप-ध्यान व पुण्यकर्म का फल ८६००० गुना होता है। (पद्म पुराण)			

मई : ३. श्री वल्लभाचार्य जयंती ८. श्री परशुराम जयंती ९. अक्षय तृतीया (पूरा दिन शुभ मुहूर्त), उज्जैन कुम्भ का द्वितीय शाही स्नान १०. अंगारकी-मंगलवारी चतुर्थी (सूर्योदय से दोपहर १२-३३ तक) ११. आद्य शंकराचार्य जयंती १२. श्री रामानुजाचार्य जयंती, गंगा जयंती, गुरुपुष्यामृत योग (सूर्योदय से रात्रि १०-४७ तक) १४. विष्णुपदी संक्रांति (पुण्यकाल : सुबह १०-१६ से शाम ४-४२ तक) २०. नृसिंह जयंती, आद्य शंकराचार्य कैलास गमन २१. वैशाख स्नान समाप्त, उज्जैन कुम्भ का तृतीय शाही स्नान (मुख्य स्नान) २२. देवर्षि नारद जयंती २९. रविवारी सप्तमी (सूर्योदय से सुबह ६-२० तक)

जून — ज्येष्ठ-आषाढ़ २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
निर्जला एकादशी के व्रत से वर्षभर की समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस दिन किया गया जप, होम, दान, स्नान आदि अक्षय होता है।			१ 1 ज्येष्ठ कृ.प. अपरा एकादशी	२ 2 द्वादशी, प्रदोष व्रत	३ 3 त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि	४ 4 चतुर्दशी, अमावस्या
५ 5 अमावस्या/ज्येष्ठ शु.प. प्रतिपदा	६ 6 द्वितीया	७ 7 तृतीया	८ 8 विनायक चतुर्थी	९ 9 पंचमी	१० 10 स्कंद षष्ठी	११ 11 सप्तमी
१२ 12 अष्टमी	१३ 13 नवमी	१४ 14 दशमी (वृद्धि तिथि), षडशीति संक्रांति	१५ 15 दशमी	१६ 16 निर्जला एकादशी	१७ 17 द्वादशी, प्रदोष व्रत	१८ 18 त्रयोदशी
१९ 19 चतुर्दशी, वट पूर्णिमा	२० 20 पूर्णिमा	२१ 21 आषाढ़ कृ.प. प्रतिपदा	२२ 22 द्वितीया	२३ 23 तृतीया, संकष्ट चतुर्थी	२४ 24 चतुर्थी	२५ 25 पंचमी
२६ 26 षष्ठी, रविवारी सप्तमी	२७ 27 सप्तमी	२८ 28 अष्टमी	२९ 29 नवमी	३० 30 दशमी/योगिनी एका.	वर्षा ऋतु २० जून से २१ अगस्त तक	

जून : ४. वटसावित्री व्रत (अमावस्यांत पक्ष) ५. गंगा दशहरा प्रारम्भ, विश्व पर्यावरण दिवस ७. महाराणा प्रताप जयंती, छत्रसाल जयंती ८. गुरु अर्जुनदेव शहीदी दिवस ९. गुरुपुष्यामृत योग (सूर्योदय से सुबह ७-३२ तक) १०. संत टेऊँराम पुण्यतिथि १४. षडशीति संक्रांति (पुण्यकाल : दोपहर १२-३१ से सूर्यास्त) १६. गायत्री जयंती १७. वटसावित्री व्रतारम्भ (पूर्णिमांत पक्ष) २०. देवस्नान पूर्णिमा, संत कबीर जयंती, दक्षिणायन आरम्भ (पुण्यकाल : सूर्योदय से सूर्यास्त) २६. रविवारी सप्तमी (दोपहर २-२१ से २७ जून सूर्योदय तक)

हिन्दू पंचांग के बारह महीनों के क्रम में पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वर्षभर की सभी तिथियों में इसलिए सबसे अधिक महत्व रखती है क्योंकि मान्यता के अनुसार इसी तिथि पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की।

इस तिथि को प्रथम स्थान मिला, इसलिए इसे प्रतिपदा कहा गया है।

विक्रम

20

जब ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ किया उस समय इसे प्रवरा तिथि सूचित किया था, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम। इस अर्थ में यह वर्ष का सर्वोत्तम दिन है जो सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी कामों में, सभी क्षेत्रों में जो भी कर्म करें, उनमें हमारा स्थान और हमारे कर्म लोक कल्याण की दृष्टि से श्रेष्ठ स्थान पर रखे जाने योग्य हों। इसे संवत्सर प्रतिपदा भी कहते हैं।

संवत् 73

जुलाई — आषाढ़-श्रावण २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
३१ 31 द्वादशी/त्रयोदशी, प्रदोष व्रत	१९ जुलाई : गुरुपूर्णिमा एवं 'ऋषि प्रसाद' जयंती। १५ जुलाई से ११ नवम्बर तक, चतुर्मास : साधना हेतु अमृततुल्य काल ❀ सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की १०८ परिक्रमा करने से दरिद्रता मिटती है।				१ 1 आषाढ़ कृ.प. योगिनी एकादशी, द्वादशी	२ 2 त्रयोदशी, शनिप्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
३ 3 चतुर्दशी	४ 4 सोमवती अमावस्या	५ 5 आषाढ़ शु.प. प्रतिपदा	६ 6 द्वितीया	७ 7 तृतीया, विनायक चतुर्थी	८ 8 चतुर्थी	९ 9 पंचमी
१० 10 षष्ठी, रविवारी सप्तमी	११ 11 सप्तमी	१२ 12 अष्टमी	१३ 13 नवमी	१४ 14 दशमी	१५ 15 देवशयनी एकादशी	१६ 16 द्वादशी, संक्रांति
१७ 17 त्रयोदशी, प्रदोष व्रत	१८ 18 चतुर्दशी	१९ 19 गुरुपूर्णिमा, 'ऋषिप्रसाद' जयंती	२० 20 श्रावण कृ.प. प्रतिपदा	२१ 21 द्वितीया	२२ 22 तृतीया	२३ 23 संकष्ट चतुर्थी
२४ 24 पंचमी	२५ 25 षष्ठी	२६ 26 सप्तमी	२७ 27 बुधवारी अष्टमी	२८ 28 नवमी	२९ 29 दशमी	३० 30 कामिका एकादशी

जुलाई : ४. सोमवती अमावस्या (सूर्योदय से शाम ४-३२ तक) ६. भगवान जगन्नाथ रथयात्रा, रमजान ईद १०. रविवारी सप्तमी (दोपहर ३-०१ से ११ जुलाई सूर्योदय तक), संत टेऊँराम जयंती १५. चतुर्मास व्रतारम्भ १६. संक्रांति (पुण्यकाल : सूर्योदय से सुबह १०-१६ तक) १९. गुरुपूर्णिमा, संन्यासी चतुर्मासारम्भ, ऋषि प्रसाद जयंती, अमरनाथ यात्रा प्रारम्भ २०. पूर्णिमांत श्रावण मासारम्भ २७. बुधवारी अष्टमी (सूर्योदय से दोपहर ३-३३ तक)

अगस्त — श्रावण-भाद्रपद २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
शरद ऋतु : २१ अगस्त से २१ अक्टूबर तक	१ 1 श्राव कृ.प. चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि	२ 2 अमावस्या	३ 3 श्रावण शु.प. प्रतिपदा	४ 4 द्वितीया	५ 5 तृतीया	६ 6 विनायक चतुर्थी
७ 7 नाग पंचमी	८ 8 षष्ठी (वृद्धि तिथि)	९ 9 षष्ठी	१० 10 सप्तमी, बुधवारी अष्टमी	११ 11 अष्टमी	१२ 12 नवमी	१३ 13 दशमी
१४ 14 पुत्रदा एकादशी	१५ 15 द्वादशी, सोमप्रदोष व्रत	१६ 16 त्रयोदशी, विष्णुपदी संक्रांति	१७ 17 चतुर्दशी, पूर्णिमा	१८ 18 राखी/श्रावणी पूर्णिमा	१९ 19 भाद्रपद कृ.प. प्रतिपदा	२० 20 द्वितीया
२१ 21 तृतीया/संकष्ट चतुर्थी	२२ 22 पंचमी	२३ 23 षष्ठी	२४ 24 सप्तमी	२५ 25 जन्माष्टमी	२६ 26 नवमी	२७ 27 दशमी
२८ 28 अजा एकादशी	२९ 29 द्वादशी, सोमप्रदोष व्रत	३० 30 त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि	३१ 31 चतुर्दशी, अमावस्या	रक्षाबंधन पर्व पर धारण किया हुआ रक्षासूत्र सम्पूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्षभर मनुष्य रक्षित हो जाता है। (भविष्य पुराण)		

अगस्त : १. लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि ३. अमावस्यांत श्रावण मासारम्भ ५. हरियाली तृतीया ७. नाग पंचमी ९. 'अंग्रेजो ! भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस १०. संत तुलसीदासजी जयंती, बुधवारी अष्टमी (सुबह १०-३१ से ११ अगस्त सूर्योदय तक) १५. स्वतंत्रता दिवस १६. विष्णुपदी संक्रांति (पुण्यकाल : दोपहर १२-१५ से शाम ६-४१ तक) १७. पतेती १८. श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, संस्कृत दिवस, श्रावणी उपाकर्म, अमरनाथ यात्रा समाप्त २५. जन्माष्टमी

सितम्बर — भाद्रपद-आश्विन २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
५ सितम्बर, गणेश चतुर्थी : 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप और गुड़मिश्रित जल से गणेशजी को इस दिन स्नान कराने एवं दूर्वा व सिंदूर की आहुति देने से विघ्न-निवारण होता है तथा मेधाशक्ति बढ़ती है।				१ 1 भाद्रपद कृ.प. अमावस्या	२ 2 भाद्रपद शु.प. प्रतिपदा	३ 3 द्वितीया
४ 4 तृतीया	५ 5 गणेश चतुर्थी	६ 6 ऋषि पंचमी	७ 7 षष्ठी	८ 8 सप्तमी	९ 9 राधाष्टमी	१० 10 नवमी (वृद्धि तिथि)
११ 11 नवमी	१२ 12 दशमी	१३ 13 पद्मा एकादशी	१४ 14 द्वादशी/त्रयोदशी, प्रदोष व्रत	१५ 15 अनंत चतुर्दशी	१६ 16 प्रोष्ठपदी पूर्णिमा, षडशीति संक्रांति	१७ 17 आश्विन कृ.प. प्रतिपदा
१८ 18 द्वितीया	१९ 19 तृतीया, संकष्ट चतुर्थी	२० 20 मंगलवारी चतुर्थी	२१ 21 पंचमी/षष्ठी	२२ 22 सप्तमी	२३ 23 अष्टमी	२४ 24 नवमी
२५ 25 दशमी	२६ 26 इंदिरा एकादशी	२७ 27 द्वादशी	२८ 28 त्रयोदशी, प्रदोष व्रत	२९ 29 चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि	३० 30 सर्वपित्री दर्श अमावस्या	श्राद्ध करने से दीर्घायु, लक्ष्मी, पुत्र-पौत्र की प्राप्ति होती है

सितम्बर : ४. हरितालिका तीज, वराह जयंती ५. गणेश-कलंक चतुर्थी, चन्द्रदर्शन निषिद्ध (चन्द्रास्त : रात्रि ९-३३), गणेश महोत्सव प्रारम्भ, शिक्षक दिवस ६. ऋषि पंचमी १२. बकरी ईद १३. वामन जयंती १४. राष्ट्रभाषा दिवस १५. अनंत चतुर्दशी, गणेश महोत्सव समाप्त १६. मांद्य चन्द्रग्रहण (भारत में दिखेगा, नियम पालनीय नहीं हैं), षडशीति संक्रांति (पुण्यकाल : दोपहर १२-१३ से शाम ६-३७ तक), महालय श्राद्धारम्भ २०. मंगलवारी चतुर्थी (सूर्योदय से दोपहर ११-५९ तक) २५. रविपुष्यामृत योग (दोपहर २-३७ से २६ सितम्बर सूर्योदय तक) २९. आग-दुर्घटना-अस्त्र-शस्त्र-अपमृत्यु से मृतक का श्राद्ध ३०. सर्वपित्री दर्श अमावस्या

अक्टूबर — आश्विन-कार्तिक २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
३० 30 अमावस्या, दीपावली	३१ 31 कार्तिक शु.प. बलि प्रतिपदा	२ अक्टूबर : पूज्य संत श्री आशारामजी बापू का ५३वाँ आत्मसाक्षात्कार दिवस ❀ दीपावली की रात्रि में जागरण कर ॐ या गुरुमंत्र का जप करना विशेष फलदायी है। हेमंत ऋतु : २१ अक्टूबर से २० दिसम्बर तक				१ 1 आश्विन शु.प. प्रतिपदा (वृ.ति.)
२ 2 प्रतिपदा	३ 3 द्वितीया	४ 4 तृतीया, मंगलवारी चतुर्थी	५ 5 विनायक चतुर्थी	६ 6 पंचमी	७ 7 षष्ठी	८ 8 सप्तमी
९ 9 महाष्टमी	१० 10 महानवमी	११ 11 विजयादशमी	१२ 12 पापांकुशा एकादशी	१३ 13 द्वादशी, प्रदोष व्रत	१४ 14 त्रयोदशी	१५ 15 चतुर्दशी, शरद पूर्णिमा
१६ 16 पूर्णिमा/कार्तिक कृ.प. प्रतिपदा	१७ 17 द्वितीया, संक्रांति	१८ 18 तृतीया	१९ 19 संकष्ट चतुर्थी, करवा चौथ	२० 20 पंचमी	२१ 21 षष्ठी	२२ 22 सप्तमी
२३ 23 अष्टमी	२४ 24 नवमी	२५ 25 दशमी	२६ 26 रमा एकादशी	२७ 27 द्वादशी, प्रदोष व्रत	२८ 28 धन त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि	२९ 29 नरक चतुर्दशी

अक्टूबर : १. शारदीय नवरात्र प्रारम्भ २. पूज्य संत श्री आशारामजी बापू का ५३वाँ आत्मसाक्षात्कार दिवस, महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, नशामुक्ति दिवस ४. मंगलवारी चतुर्थी (दोपहर १२-३५ से ५ अक्टूबर सूर्योदय तक) ११. विजयादशमी (पूरा दिन शुभ मुहूर्त), दशहरा १२. मोहर्रम (ताजिया) १५. शरद पूर्णिमा १६. कार्तिक स्नानारम्भ १७. संक्रांति (पुण्यकाल : सूर्योदय से दोपहर १२-२४ तक) २३. रविपुष्यामृतयोग (सूर्योदय से रात्रि ८-४० तक) २६. ब्रह्मलीन मातुश्री श्री माँ महँगीबा महानिर्वाण दिवस २८. धनतेरस, धन्वंतरि जयंती २९. नरक चतुर्दशी ३०. दीपावली, स्वामी रामतीर्थ जयंती एवं पुण्यतिथि ३१. वि.सं. २०७३ नूतन वर्षारम्भ (गुज.-महा.), बलि प्रतिपदा (पूरा दिन शुभ मुहूर्त), सरदार पटेल जयंती

नवम्बर — कार्तिक-मार्गशीर्ष २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
देवउठी एकादशी के दिन गुरु का पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं व भगवान विष्णु की कपूर से आरती करने पर अकाल मृत्यु नहीं होती।		१ 1 कार्तिक शु.प. द्वितीया, भाईदूज	२ 2 तृतीया	३ 3 विनायक चतुर्थी (वृ.ति.)	४ 4 चतुर्थी	५ 5 लाभ पंचमी
६ 6 षष्ठी, रविवारी सप्तमी	७ 7 सप्तमी	८ 8 गोपाष्टमी	९ 9 आंवला नवमी	१० 10 दशमी, देवउठी एकादशी	११ 11 विष्णुप्रा देवउठी एकादशी/द्वादशी	१२ 12 त्रयोदशी, शनिप्रदोष व्रत
१३ 13 चतुर्दशी	१४ 14 त्रिपुरारी पूर्णिमा	१५ 15 मार्गशीर्ष कृ.प. प्रतिपदा	१६ 16 द्वितीया, विष्णुपदी संक्रांति	१७ 17 तृतीया/संकष्ट चतुर्थी	१८ 18 पंचमी	१९ 19 षष्ठी
२० 20 रविवारी सप्तमी	२१ 21 अष्टमी	२२ 22 नवमी	२३ 23 दशमी	२४ 24 उत्पत्ति एका. (वृद्धि तिथि)	२५ 25 उत्पत्ति एकादशी	२६ 26 द्वादशी, शनिप्रदोष व्रत
२७ 27 त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि	२८ 28 चतुर्दशी, सोमवती अमावस्या	२९ 29 अमावस्या	३० 30 मार्गशीर्ष शु.प. प्रतिपदा	११ नवम्बर, विष्णुप्रा देवउठी एकादशी : इस दिन उपवास करने से १००० एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। (पद्म पुराण)		

नवम्बर : १. भाईदूज ५. लाभ पंचमी ६. रविवारी सप्तमी (दोपहर १२-१७ से ७ नवम्बर सूर्योदय तक) ९. साँई श्री लीलाशाहजी महाराज महानिर्वाण दिवस १०. भीष्मपंचक व्रत प्रारम्भ ११. तुलसी विवाह प्रारम्भ १४. गुरु नानक जयंती, भीष्मपंचक व्रत समाप्त १६. विष्णुपदी संक्रांति (पुण्यकाल : सूर्योदय से दोपहर १२-२४ तक) २०. रविवारी सप्तमी (सूर्योदय से रात्रि १-५८ तक) २४. गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस २७. श्री ज्ञानेश्वर पुण्यतिथि २८. सोमवती अमावस्या (दोपहर ३-२१ से २९ नवम्बर सूर्योदय तक)

दिसम्बर — मार्गशीर्ष-पौष २०७३

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
शिशिर ऋतु : २१ दिसम्बर से १७ फरवरी २०१७ तक। २५ दिसम्बर, तुलसी पूजन दिवस : शुद्ध भाव व भक्ति से तुलसी के पौधे की १०८ परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है।				१ 1 मार्गशीर्ष शु.प. द्वितीया	२ 2 तृतीया	३ 3 विनायक चतुर्थी
४ 4 पंचमी	५ 5 स्कंद षष्ठी	६ 6 सप्तमी	७ 7 बुधवारी अष्टमी	८ 8 नवमी	९ 9 दशमी	१० 10 मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती
११ 11 द्वादशी, प्रदोष व्रत	१२ 12 त्रयोदशी	१३ 13 चतुर्दशी/पूर्णिमा	१४ 14 पौष कृ.प. प्रतिपदा	१५ 15 द्वितीया, षडशीति संक्रांति	१६ 16 तृतीया, संकष्ट चतुर्थी	१७ 17 चतुर्थी
१८ 18 पंचमी	१९ 19 षष्ठी	२० 20 सप्तमी	२१ 21 बुधवारी अष्टमी	२२ 22 नवमी	२३ 23 दशमी	२४ 24 सफला एकादशी
२५ 25 द्वादशी	२६ 26 त्रयोदशी (वृ.ति.), सोमप्रदोष व्रत	२७ 27 त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि	२८ 28 चतुर्दशी, अमावस्या	२९ 29 अमावस्या	३० 30 पौष शु.प. प्रतिपदा	३१ 31 द्वितीया

दिसम्बर : ७. बुधवारी अष्टमी (सूर्योदय से रात्रि २-०५ तक) १०. श्रीमद्भगवद्गीता जयंती १३. दत्तात्रेय जयंती, ईद-ए-मिलाद १५. षडशीति संक्रांति (पुण्यकाल : दोपहर १२-३३ से सूर्यास्त) २१. बुधवारी अष्टमी (सूर्योदय से रात्रि ८-१९ तक) २५. तुलसी पूजन दिवस, पं. मालवीय जयंती, क्रिसमस

विदेशी वस्तु त्याग कर - बोलो वन्देमातरम्

वस्तु	विदेशी उत्पादन का बहिष्कार करे।
नहाने का साबुन	लक्स, लिरिल, लाईफबॉय, पियर्स, रेक्सोना, हमाम, जय, मोती, कैमे, डॅव, पॉंड्स, पामऑलिव, जॉन्सन, क्लिएरसिल, डेटॉल, लेसान्सी, जस्मीन, गोस्डमिस्ट, लक्मे, ॲमवे, क्वांटम, मार्गो, फा, नीम
कपड़े धोने का साबुन	सनलाईट, व्हील, एरियल, चेक, डबल, ट्रीलो, ५०१, ओके, की, रिबेल, ॲमवे, क्वांटम, सर्फ एक्सेल, रिन, विमबार, बिझ, रॉबिन ब्लू, और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के अन्य उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	जॉन्सन, पॉण्ड्स, ओल्ड स्पाईस, क्लियरसिल, ब्रिलक्रीम, फेयर एण्ड लवली, वेल्वेट, मेडीकेयर, लेवेंडर, नायसिल, शॉवर टू शॉवर, क्यूटीकुरा, लिरिल, लॅक्मे, डेनिम, ऑरगॉनिक्स, पेन्टीन, रूट्स, हेड एण्ड शोल्डर, ॲमवे, क्वांटम, क्लीनिक, निहार, कोको केयर, ग्लैक्सो, नवराट्सि, मॉरटिम आदि
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	कॉलगेट, सिबाका, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिग्नल, मॅक्लीन्स, प्रुडंट, अैमवे, क्वांटम, अक्वा फ्रेश, नीम, ओरल–बी, फोरहॅन्स
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	पामऑलिव, ओल्ड स्पाईस, निविया, पॉन्डस्, प्लैटिनम, जिलेट, सेवेन–ओ–क्लाक, विलमैन, विल्टेज, इरॅस्मिक, स्विस, लॅक्मे, डेनिम
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	ब्रिटानिया–गुड डे व ब्रेड, टाईगर, मैरी, नेसले, कॅडबरी, बोर्नव्हिटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, मिल्कमेड, किसान, मैगी, फैरेक्स, अनिकस्प्रे, कॉम्प्लान, किटकैट, चार्ज, एक्लेअर, मीलो, मॉडर्न ब्रेड, माल्टोवा, व्हिवा, माइलो, मिल्कफूड
चाय कॉफी	ब्रुक बॉंड, ताजमहल, रेड–लेबल, डायमंड, लिप्टन, ग्रीन लेबल, टाईगर, नेसकॅफे, नेसले, डेल्का, ब्रू, सनराईज, थ्री फ्लावर्स
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	लेहर, पेप्सी, सेवन–अप, मिरडा, टीम, कोका–कोला, मॅकडॉवेल सोडा, मॅंगोला, गोल्डस्पॉट, लिम्का, सिट्रा, थम्स–अप, स्प्रिंट, डयूक्स, फॅन्टा, कॅडबरी, कॅनडा ड्राय, क्रश
पीने का पानी	ॲक्वाकिना, किन्ले, नेसले नॅचरल
आईस्क्रीम	कॅडबरी, डॉलॉप, नाईस, ब्रुक ब्रांड के उत्पादन, क्वालिटी वॉल्स, कॉरनेली, बास्कीन–रॉबिन्स, यांकी–डूडल्स, कॉरनेट्टो
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	डालडा, क्रिस्टल, लिप्टन, अन्नपूर्णा नमक, आटा और चपाती, मॅगी, किसान, तरला, ब्रुक–बॉंड, पिल्सबरी आटा, कैप्टन कुक नमक और आटा, मॉडर्न चपाती, कारगिल आटा, अंकल चिप्स, लेज, लेहर
विद्युत उपकरण गहोपयोगी वस्तु	जीईसी, फिलिप्स, सोनी, टीडीके, निप्पो, नॅशनल–पैनासोनिक, शार्प, जीई, व्हर्लपूल, सैमसंग, देवू, तोशीबा, एल जी, हिताची, थॉमसन, इलेक्ट्रोलक्स, अकाई, सानसूई, केनवुड, आइवा, ऑल्विन फ्रिज, कैरियर, कोंका, टपरवेयर, जापान लाईफ, ओमेगा, टाइमेक्स, राडो, पायोनियर, टपरवेअर, जपान लाईफ
घड़ियां	ओमेगा, टाईमेक्स, टीसीएल
लेखन सामग्री	पार्कर, पायलट, विंडसर–न्यूटन, फैबर–कैसेल, लक्ज़र, बिक, मॉंट ब्लैक, कोरस, अेस, रोटरिंग, वेटसिंग
जूते, चप्पल पॉलिश	बाटा, प्यूमा, पॉवर, चेरी–ब्लॉसम, आदिदास, रिबॉक, नाइक, लीकूपर, गैसोलीन
तैयार कपड़े	ली के सभी उत्पाद, बर्लिंगटन, ॲरो, लकोस्ट, सॅनफिस्को, लेविस, पेपे जीन्स, रैंगलर, बेनेटोन, रीड एण्ड टेलर, बायफोर्ड

दानवीरता की आड़ में कमाई?

दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स और उसकी पत्नी के नाम से एक अधिष्ठान दुनिया में दानवीरता की मिसाल के नाम से जाना जाता रहा है। कई वर्षों से दुनिया को रोगमुक्त करने के नाम पर बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विभिन्न देशों के टीकाकरण कार्यक्रमों में दान देने का काम करता रहा है। लेकिन हाल ही में आई एक अंतर्राष्ट्रीय रपट ने दावा किया है कि बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के फायदे के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का काम कर रही है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्य कलापों पर नजर रखने के लिए उसे 'निगरानी सूची' में रखा है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने गुजरात की टीस्टा सेट्लवाद की एनजीओ को आर्थिक सहायता देने के लिए अमरीका की फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी सूची में रखने का फैसला किया था।

मोदी सरकार बनने के बाद सरकार ने एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकत विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले 15000 विदेशी संगठनों के लाईसेंस रद्द कर दिये थे, लेकिन बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी क्योंकि यह उस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकत ही नहीं था।

– डॉ. अश्वनी महाजन

रजिस्टर्ड भी नहीं है फाउंडेशन

गौरतलब है कि किसी भी विदेशी एजेंसी को भारत के कानूनों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास फॉरेन काट्रीब्यूशन रेगूलेशन एक्ट (एफ.सी.आर.ए.) के तहत पंजीकरण करवाना होता है, लेकिन हैरानी का विषय यह है कि यह फाउंडेशन इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। गौरतलब है कि मोदी सरकार बनने के बाद सरकार ने एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले 15000 विदेशी संगठनों के लाईसेंस रद्द कर दिये थे, लेकिन बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी क्योंकि यह उस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ही नहीं था। वास्तव में यह संगठन फॉरेन एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत एक लाईजॉन कार्यालय के नाते काम करता है और इसलिए एफसीआरए के प्रावधानों से बचा रहा है। 'फेमा' के अंतर्गत किसी लाईजॉन आफिस को काम करने की अनुमति देने का काम रिजर्व बैंक करता है, लेकिन उसका नियमन और नियंत्रण करने का रिजर्व बैंक के पास काई प्रावधान ही नहीं है।

'ग्लोबल जस्टिस नाऊ' नाम की इंग्लैंड से संचालित एक संस्था की हालिया रिपोर्ट (जिसके आधार पर भारत सरकार ने 'बिल एण्ड मेलिडा गेट्स फाऊंडेशन' को सतर्कता सूची पर रखा है), में कहा गया है कि फाऊंडेशन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर खासतौर पर कृषि और दवा क्षेत्र में लगी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में नीतियां, बनवाने के लिए संलग्न है।

सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ावा देते हुए, यह फाऊंडेशन बड़ी दवा कंपनियों की भूमिका को औचित्य प्रदान कर रही है। फाऊंडेशन के अंतर्गत चल रहे प्रकल्पों 'ग्लोबल फण्ड टू फाईट एड्स' 'ट्यूबर क्लोसिय एण्ड मलेरिया' (जीएफएटीएम) और जीएवीए एलांयस

फाऊंडेशन के प्रकल्प हैं जिन के बोर्ड पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फारमूसिटिकल मैन्युफैक्चर्स की सदस्य कंपनियों के प्रतिनिधि रहते हैं, जिनमें प्रमुख कंपनियां है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाईन, मर्क, नॉवरेतिस, फाईजर इत्यादि।

इस विषय के जानकर डॉक्टरों का कहना है कि ये कंपनियां अपने टीकों की बिक्री बढ़ाने हेतु विविध प्रकार के टीकों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल करवा चुकी हैं और कई अन्य टीकों का राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करवाने हेतु कार्यवाही चल रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में हैपेटाइटस–बी, एच–1बी, पोलियो का टीके समेत बड़ी संख्या में नए टीकों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किया गया, जिनपर हजारों करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय टीकारण कार्यक्रम में पूर्व में प्रचलित डी.टी.पी. त्रय के साथ अब दो और टीके हैपेटाइटस–बी और एच–1बी शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि नए टीकाकरण कार्यक्रम को देश में वैज्ञानिक अध्यनों और नेशनल टेकनीकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इडिया की सिफारिशों पर लागू किया गया है। गौरतलब है कि इस टीकाकरण की शुरू करवाने के लिए 'बिल एवं मिलेंडा गेट्स फांउडेशन' ने प्रारंभ में वित्तीय सहयोग किया और अब राष्ट्रीय टीकाकरण में ये दोनों शामिल हो जाने के बाद इसका सारा भार भारत सरकार पर आ गया है। गौरतलब है कि हर साल 2 करोड़ 50 लाख नवजात शिशु को ये टीके लगाए जाते हैं, जिन पर प्रति शिशु 525 रूपए खर्च हो रहे हैं। इससे पहले डीटीपी टीकाकरण में सरकार के मात्र 5 रूपए ही खर्च होते थे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इन टीकों के बारे में दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस अस्पताल के शिशु चिकित्सा विभागाध्यक्ष डा. जेकॉब पुलियल ने ब्रिटानिया मैडिकल जरनल में प्रकाशित अपने शोध लेख में कहा है कि देश में जिस हैपेटाइटस–बी की रोकथाम के लिए यह टीकाकरण हो रहा है, उसका प्रभाव देश में इतना नहीं है कि उसके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम हो। जहां तक संक्रमण के कारण होने वाले हैपेटाइटस–बी का सवाल है, उसे रोकपाने में यह टीका निष्प्रभावी है।

दूसरी ओर ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें 'बिल एंड मिलेंडा गेट्स फांउडेशन' द्वारा नए टीकों के ट्रायल के ऐसे अनैतिक प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। कुछ समय पहले इकॉनोमिक टाइम्स ने खबर के माध्यम से इन अनैतिक प्रयोगों का खुलासा किया था। यानि कहा जा सकता है कि अपने टीकाकरण के बाजार को पोषित करने के लिए यह फांउडेशन अनैतिक प्रयोग कराने में भी सहयोगी बन रही है। फांउडेशन और टीका बाजार के बीच संबंध इस बात से पता चलता है कि 'गवी' जिसका वित्तीय पोषण फांउडेशन की बीएमजीएफ करती है, ने देश में पैंटा वैलेंट नाम की टीके को शामिल करने के लिए 1650 लाख डालर की सहायता देना स्वीकार किया है और उसके द्वारा अगले पांच सालों के लिए 145 रूपए प्रति टीका की दर से सब्सिडी दी जाएगी और उसके बाद सारी लागत भारत सरकार को उठानी होगी।

देश में टीकाकरण कार्यक्रम पर गेट्स फाउंडेश हावी है और गेट्स फाउंडेशन की कार्य पद्धति में सभी बड़ी फार्मा कंपनियां सीधे संलग्न हैं।

फांउडेशन प्रभावित कर रही है सरकारी नीतियां

हैरानी का विषय है कि एक ओर सरकार का गृह मंत्रालय गेट्स फाउंडेशन को विशेष निगरानी सूची में रख रहा है तो दूसरी ओर वही फाउंडेशन देश की स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित कर रही है। मार्च 11, 2016 को भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 'बिल मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन' की सह अध्यक्षा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मिली और सरकार के टीकाकरण सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रशंसा की और स्वास्थ्य मंत्री ने भी भारत सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की।

गौरतलब है कि जिस टीकाकरण कार्यक्रम को भारत सरकार चला रही है, उसके बारे में सिफारिश 'नेशनल टेकनिकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन' द्वारा की जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस ग्रुप में 'गेट्स फाउंडेशन' का दबदबा है। यह भी ध्यान में आया है कि इस ग्रुप पर सूचना के अधिकार के नियम लागू नहीं होते, और सूचना मांगने पर यह कहा जाता है कि यह सरकार का हिस्सा नहीं है। यानि कुल मिलाकर देश में टीकाकरण कार्यक्रम पर गेट्स फाउंडेश हावी है और गेट्स फाउंडेशन की कार्य पद्धति में सभी बड़ी फार्मा कंपनियां सीधे संलग्न हैं। जाहिर है कि हमारे देश का टीकाकरण कार्यक्रम सरकार द्वारा कम और कंपनियों द्वारा ज्यादा संचालित हो रहा है। इस बावत जिन वैज्ञानिक अध्ययनों की बात की जा रही है, वे भी इन कंपनियों द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। ऐसे में देश में कौन से टीके होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, उसके बारे में टीकों को बनाने वाली कंपनियां ही तय कर रही हैं। ❑❑

'आधार' बनें पारदर्शिता का आधार

भारत ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में संभवत् राजीव गांधी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होगें जिन्होंने व्यवस्था में भ्रष्टाचार की व्यापकता का खुलकर इजहार करते हुए कहा था कि केंद्र के भेजे एक रुपये का केवल 15 पैसे ही सही व्यक्ति तक पहुंच पाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि राजीव गांधी की सरकार और उसके बाद बनने वाली सरकारें भी इस बात का कोई समाधान नहीं कर सकी कि कैसे सरकार द्वारा दिया जाने वाला पैसा आम आदमी तक पहुचें। परंतु अभी हाल ही में सरकार द्वारा आधार बिल को लोकसभा में रखते हुए अरुण जेटली ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस बिल से सरकार को लाभार्थियों तक सीधे सहायता पहुँचायी जा सकेगी तथा जन–कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हालाकि विपक्ष यह कहते हुए इस बिल का विरोध कर रहा है कि इससे देश के नागरिकों की निजता खतरे में पड़ जायेगी तथा सरकारी एवं कोई अन्य एजेंसी भी नागरिकों की सब प्रकार की जानकारियां आसानी से जुटा लेगी। इस विधेयक को मनी बिल के नाते पेश करने पर भी विरोध के स्वर उठ रहे है तथा आरोप लग रहा है कि सरकार बहस से बचने के लिए ये कदम उठा रही है। इस विधेयक का सही आकलन करने के लिए इन सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।

आधार बिल जनता के पैसों के उपयोग को युक्तिता और पारदर्शिता देने में सक्षम है तथा कांग्रेस सरकार के 2010 में लाये गये बिल से ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी है। कांग्रेस द्वारा लाये गये बिल में भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार पाने के योग्य था जबकि मोदी सरकार के बिल में ये प्रावधान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो सिर्फ वो ही अपना आधार बनवा सकता है।

– डॉ. सुभाष शर्मा

इसमें कोई शक नहीं कि भारत में पानी, आटा, दाल, चावल, किरोसीन, गैस सिलेन्डर, बीज, खाद तथा अन्य कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश का गरीब आदमी सरकार की सब्सिडी पर ही निर्भर है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के आकड़ों के अनुसार 2015–16 में 3.78 लाख करोड़ रुपये, जोकि भारत की जी.डी.पी. का लभगभ 4.2 प्रतिशत है, सब्सिडी के रुप में विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिये गये हैं। करदाताओं की मेहनत की कमाई से सरकार के पास आने वाला यह धन लाभार्थी तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। पिछले 20 महीनों में मोदी सरकार प्रतिबद्धता

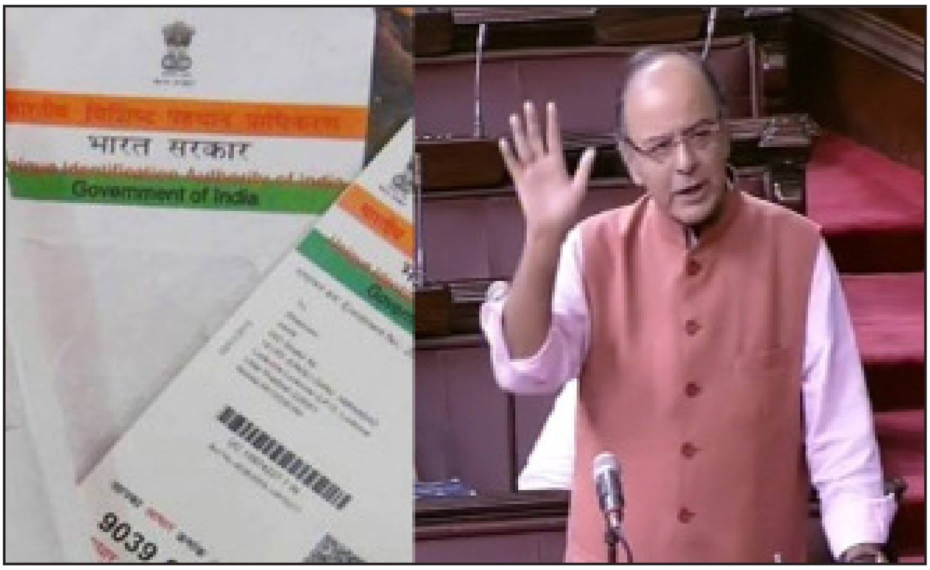

से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार ने ना केवल 'पहल' योजना से भारतीय संचित निधि के लगभग 15 हजार करोड़ रु. बचाये बल्कि आधार को गैस सब्सिडी से जोड़कर अब तक 15.1 करोड़ लाभार्थियों को 29 हजार करोड़ रुपये सीधे स्थानान्तरित किये गये है।

'जैम' को अगर बापू के साथ जोड़ दिया जाय तो जनता के लाखों करोड़ रुपये बच सकते है, जिसके लिए आधार अनिवार्य है।

आधार बिल जनता के पैसों के उपयोग को युक्तिता और पारदर्शिता देने में सक्षम है तथा कांग्रेस सरकार के 2010 में लाये गये बिल से ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी है। कांग्रेस द्वारा लाये गये बिल में भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार पाने के योग्य था जबकि मोदी सरकार के बिल में ये प्रावधान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो सिर्फ वो ही अपना आधार बनवा सकता है। इसके साथ ही क्लाज नौ ये स्पष्ट करता है कि आधार का नागरिकता से कोई सरोकार नहीं है। इस बिल का का सेक्शन–7 ये कहता है कि सरकार किसी भी सब्सिडी या सेवा के लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है, जो कि एक सराहनीय पहल है। इसको भारत के उच्चतम न्यायालय के हाल ही में आये निर्णय से वैधानिक समर्थन भी प्राप्त है। इस बिल में एक और सराहनीय बात है कि आधार कार्ड में फोटो पहचान और बायोमेट्रिक, नाम, जन्मदिन और पता होगा लेकिन धर्म और जाति की पहचान नहीं होगी। देश से जातिवाद और सांप्रदायिकता समाप्त करने के लिए ये अच्छी यह शुरुआत है।

सोशल मीडिया और पारदर्शिता के युग में सूचनाओं को गुप्त रखना एक बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन मोदी सरकार का आधार बिल इस कसौटी पर भी खरा उतरता है क्योंकि इसके क्लाज 29(1) में स्पष्ट उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति की फिंगरप्रिंट सहित अन्य सूचनायें जो एकत्र की जाती है वो किसी भी व्यक्ति या संस्था से शेयर नहीं की जायेगी। ये सूचनायें आइटी एक्ट 2000 के तहत संरक्षित रहेगी। कभी भी किसी व्यक्ति की इन सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का आदेश विधिपूर्वक ना लिया गया हो। अगर फिर भी सेंट्रल डाटा रिपोजिटरी से ये डाटा किसी भी व्यक्ति ने बिना प्रकिया के पालन के निकालने की कोशिश की तो उसे तीन वर्ष की जेल और दस लाख के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं सक्षम प्रधिकारी को भी आधार बिल में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि भारत सरकार का कोई भी ज्वाइन्ट सेक्रेटरी या जिला न्यायाधीश या भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही राष्ट्र सुरक्षा के संदर्भ में इन सूचनाओं को साझा कर सकते है। ये प्रावधान विपक्ष की सभी आशंकाओ को निर्मूल तथा मोदी सरकार की आम नागरिकों की निजता तथा राष्ट्र सुरक्षा के प्रति गंभीरता को भी प्रदर्शित करता है।

कांग्रेस ये जानती है कि मोदी सरकार के गुड गवर्नेंस की पहल को "आधार" और भी मजबूत करेगा, जिसका लाभ देश के गरीब, दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को मिलना तय है। शायद यही बात कांग्रेस को नहीं पच रही। गरीबों और वंचितों को बिना बिचौलिये का लाभ देने के लिए मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन बनाया है, जो समाजिक सुरक्षा की सब्सिडी को सीधे लाभार्थी तक पहुचाने के लिए कार्य कर रहा है। 'जैम' मतलब जनधन आधार और मोबाइल। इसका उपयोग करके कई प्रदेश सरकारों ने करोड़ों रुपये बचाये है। सबसे भ्रष्ट समझे जाने वाले वाले पीडीएस को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चार राज्यों में लागू किया गया जिससे 2300 करोड़ रुपये सरकार ने बचाये जो सराहनीय और अतुलनीय है।

'जैम' को अगर बापू (बायोमैट्रीकली आथेन्टिकेटिड फिजिकल अपडेशन) के साथ जोड़ दिया जाय तो जनता के लाखों करोड़ रुपये बच सकते है, जिसके लिए आधार अनिवार्य है। जैम और बापू को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन जैसी सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने से देश की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन निश्चित है। मोदी सरकार ने इस बिल के माध्यम से आधार को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया है, जो भारत के इतिहास में सुशासन की दिशा में सबसे मजबूत कदम साबित होगा। सरकार और लाभर्थियों के बीच के सभी तरह के बिचौलियों को समाप्त करने से सरकार द्वारा भेजा गया एक रुपया अब सीधे लाभार्थी को ही मिलेगा। ❑❑

लेखक सेंटर फॉर इकोनोमिक पॉलिसी रिसर्च, चण्डीगढ़ में निदेशक एवं स्वदेशी जारगण मंच की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य है।

डब्लूटीओ पर पुर्नविचार जरूरी

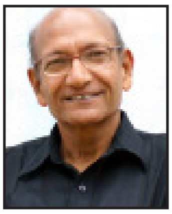

विश्व व्यापार का पहला बिंदु व्यापार यानी माल तथा सेवाओं की खरीद–बेच है। फैक्ट्रियों में उत्पादित माल के व्यापार में डब्लूटीओ की स्थापना के बाद सरलता आई है जो स्वागत योग्य है। लेकिन कषि उत्पादों के व्यापार में गतिरोध बना हुआ है। विकसित देशों ने कथित रूप से इन उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को समाप्त कर दिया है परंतु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

एनडीए सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने को है। एनडीए ने चुनाव दो मुद्धों पर जीते थे। एक मुद्धा सुशासन यानी भ्रष्टाचार से मुक्ति का था। इस मुद्धे पर सराहनीय प्रगति हुई है। ऊपर के स्तर पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आई है। नीचे के स्तर तक सुशासन के फैलने में समय लग सकता है परंतु दिशा सही है। चुनाव का दूसरा मुद्धा ''अच्छे दिन'' का था। यहां संकट गहराया है। आम आदमी का रोजगार चौपट हो गया है। इस समस्या के कई आयाम है। एक आयाम विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ द्वारा आरोपित सीमाओं का है। डब्लूटीओ के अंतर्गत अच्छे दिन आना लगभग असंभव है।

विश्व व्यापार का पहला बिंदु व्यापार यानी माल तथा सेवाओं की खरीद–बेच है। फैक्ट्रियों में उत्पादित माल के व्यापार में डब्लूटीओ की स्थापना के बाद सरलता आई है जो स्वागत योग्य है। लेकिन कृषि उत्पादों के व्यापार में गतिरोध बना हुआ है। विकसित देशों ने कथित रूप से इन उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को समाप्त कर दिया है परंतु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। दूसरे माध्यमों से विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को कृषि उत्पादन सब्सिडी दी जा रही है। जैसे अमरीका में किसानों को भूमि को पड़ती छोड़ने के लिये सब्सिडी दी जाती है। इन सब्सिडी से अन्ततः अमरीकी किसानों के लिये उत्पादित माल को सस्ता बेचना संभव हो जाता है। इस प्रकार के तमाम उपायों से विकसित देशों में कृषि उत्पादों की वास्तविक उत्पादन लागत जादा है लेकिन विश्व बाजार में वे अपने माल को सस्ता बेच रहे हैं। विकसित देशों द्वारा बेचे जा रहे इस सस्ते माल से हमारे किसान पस्त हैं। इस कठिनाई से कुछ राहत दिलाने के लिये नैरोबी में तय हुआ है कि विकासशील देश खाद्यान्न का भंडारण कर सकेंगे तथा कम समय के लिये आयात कर लगा सकेंगे। स्पष्ट है कि ये उपलब्धियां अग्निशमन सरीखी हैं। इनके लागू होने के बावजूद डब्लूटीओ की मूल

व्यवस्था के कारण हमारे किसानों पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव बना रहेगा।

हमारे किसानों द्वारा कृषि उत्पाद सस्ते उत्पादित किये जा रहे हैं परंतु विकसित देशों के द्वारा विभिन्न तरीकों से दी जा रही कृषि सब्सिडी के कारण ये देश माल को सस्ता बेच रहे हैं। विकसित देशों द्वारा दी जा रही इन अनैतिक सब्सिडी को हटाने पर नैरोबी समझौता मौन है। कैंसर के मरीज की रेडियो थैरेपी न की जाये और उसे दर्द से राहत दिलाने के लिये पेन किलर दिया जाये ऐसी व्यवस्था नैरोबी समझौते में की गई है। पेन किलर की उपयोगिता को नहीं नकारा जाना चाहिये। परंतु मूल विषय तो कैंसर के उपचार का है।

गतवर्ष नैरोबी में डब्लूटीओ की मंत्रीस्तरीय वार्ता हुई थी। इस वार्ता में भारत की कुछ उपलब्धियां रही हैं। फूड कार्पोरेशन द्वारा देश की खाद्य सुरक्षा के लिये खाद्यान्न के भंडारण को छूट मिली है। खाद्यान्न के आयातों में भारी वृद्धि की स्थिति में अल्प समय के लिये आयात कर बढ़ाने की अनुमति मिली है। विकसित देशों ने कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी पूरी तरह हटाना स्वीकार किया है। कपास के व्यापार को सभी कोटा से मुक्त कर दिया गया है। ये उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं लेकिन इनका मूल स्वरूप फायर फाइटिंग का है। अमीर देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडीयों को हटाने पर ध्यान नही दिया जा रहा है। केवल इन सब्सिडी के दुष्प्रभावों को टालने की बात की गई है।

विश्व व्यापार का दूसरा बिन्दु श्रमिकों के पलायन का है। विश्व व्यापार की वर्तमान व्यवस्था में श्रम शक्ति को माल में पैक करके माल का निर्यात किया जाता है। जैसे चैन्नई में भारतीय श्रमिकों की श्रम शक्ति को कार में पैक करके कार का निर्यात यूरोप को किया जा रहा है। विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिये जरूरी है कि भारतीय श्रम शक्ति का सीधे निर्यात किया जाये। श्रमिक के पलायन का रास्ता खोल दिया जाये। भारतीय श्रमिक यूरोप में जाकर कार का निर्माण करे तो कार की ढुलाई बच जायेगी। श्रमिकों के मुक्त पलायन का यह गंभीर विषय डब्लूटीओ की संधि में नहीं था। इसे डब्लूटीओ में जोड़ा जाना चाहिये था। नैरोबी में ऐसा नहीं हुआ।

विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिये जरूरी है कि भारतीय श्रम शक्ति का सीधे निर्यात किया जाये।

विश्व व्यापार का तीसरा बिंदु पेटेंट कानून का है। 1995 में डब्लूटीओ संधि लागू होने के पूर्व हर देश की अपनी पेटेंट व्यवस्था थी। डबलूटीओ संधि में सभी देशों के पेटेंट कानूनों को समान बना दिया गया है। इनके उलंघन होने की स्थिति में दूसरे देशों को प्रतिबंध अथवा आयात कर लगाने की छूट दे दी गयी है। वर्तमान में विकसित देशों को रायल्टी से भारी आय हो रही है इसलिये उनके लिये निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करना आवश्यक नहीं रह गया है। डब्लूटीओ की दोहा वार्ता में तय किया गया था कि पेटेंट कानून को नरम बनाया जायेगा। जन–स्वास्थ्य प्रभावित होने की स्थिति में पेटेंट कानून को निरस्त करने की व्यवस्था की गई थी। दोहा की मूल दिशा पेटेंट कानून को नरम बनाने की ओर थी। नैरोबी में इसे पलट दिया गया है। नैरोबी समझौते में कहा गया है कि दोहा समझौते पर सब देश सहमत नहीं हैं। पूर्व में सर्वसहमति से तय हुआ था कि पेटेंट कानून को नरम बनाया जायेगा। लेकिन नैरोबी में इस सहमति को निरस्त कर दिया गया है। पेटेंट कानून में नरमी लाने का रास्ता बंद हो गया है। तदानुसार विकसित देशों द्वारा पेटेंट पर रायल्टी के माध्यम से विकसित देशों की आय चूसने का रास्ता प्रशस्त हो गया है।

डब्लूटीओ की सिंगापुर वार्ता में विकसित देशों ने पुरजोर प्रयास किया था कि निवेश, सरकारी खरीद तथा कंपटीशन पॉलिसी को भी डब्लूटीओ में शामिल किया जाये। विकासशील देशों के द्वारा कड़ा विरोध किये जाने के कारण इन्होंने डब्लूटीओ के ऐजेंडे से बाहर कर दिया गया था। नैरोबी में इन्हें पुनः डब्लूटीओ के एजेंडे में शामिल कर दिया गया है। इतना जरूर कहा गया है कि इन विषयों पर सर्व सहमति से ही निर्णय लिया जायेगा। परंतु यह व्यर्थ की बात है चूंकि डब्लूटीओ में सभी फैसले सर्व सहमति से ही दिये जाते हैं।

समय आ गया है कि हम डब्लूटीओ के मूल चरित्र पर पुनर्विचार करें। अमीर देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी तथा पेटेंट कानून के माध्यम से हो रहा हमारे शोषण पर डब्लूटीओ मौन है। हमारे श्रमिकों के मुक्त पलायन को खोलने पर कोई पहल नही की गई है। इन समस्याओं का सामना किए बिना आम आदमी के अच्छे दिन नही आएंगे। अतः एनडीए सरकार को डब्लूटीओ पर सख्त रूख अपनाकर इन मूल समस्याओं का हल करना चाहिए। ❑❑

स्वातंत्र्य वीर सावरकर
व्यक्तित्व एवं कृतित्व

जिस दिन एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस दिन हमारे देश के कुछ चाटुकार भी समारोह आयोजित कर रहे थे – महान क्रांतिकारी वीर सावरकर त्रयंबकेश्वर गये हुए थे। उन्होंने ऐसा ही नजारा वहां भी देखा। उनका मन दुःखी हो गया। समारोह स्थल पर पहुंचकर उन्होंने नौजवानों से कहा ''धिक्कार है तुम्हें, जो तुम ऐसी खुशियां मना रहे हो। क्या तुम्हें यह अनुभव नहीं होता कि यह अभिषेकोत्सव नहीं, बल्कि तुम्हारी गुलामी का उत्सव है? क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि विदेशी शासके के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन तुम्हारे अपने देश एवं जाति के प्रति द्रोह की अभिव्यक्ति है?''

भारत की आजादी के आंदोलन के इतिहास में स्वांतत्र्य वीर सावरकर का अप्रतिम स्थान है। वे महान क्रांतिकारी, देशभक्त और महान संगठनवादी नेता थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनका देश प्रेम, त्याग और शौर्य युवकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा।

भारत की आजादी के आंदोलन के इतिहास में स्वांतत्र्य वीर सावरकर का अप्रतिम स्थान है। वे महान क्रांतिकारी, देशभक्त और महान संगठनवादी नेता थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनका देश प्रेम, त्याग और शौर्य युवकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा।

– डॉ. विजय वशिष्ठ

सावरकर जी का कद छोटा था लेकिन व्यक्तित्व महान था। उनके भीतर साहस और शक्ति का अद्भुत प्रकाश था। उनका हिन्दू धर्म में अटूट विश्वास था। वे जाति–पांति और छुआछूत से दूर एक महाज्ञानी ऋषि थे। वे कहते थे कि भारत की सीमा के भीतर जो भी रहता है, वह आर्य है। अखण्ड भारत की स्वतंत्रता उन्हें प्राणों से भी प्रिय थी। इसीलिए वे जीवन भर अखण्ड भारत के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए पैदा हुए, भारत के लिए चिरनिन्द्रा में सो गये। उनका जन्म, उनका जीवन एवं उनकी मृत्यु भारतीयों को सदा प्रेरणा देती रहेगी।

स्वातंत्र्य वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में 28 मई 1883 को हुआ। उनके बाबा विनायक, पिता के दामोदर, नाम को लेकर बालक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जनता ने उन्हें वीर की उपाधि से विभूषित किया, इसलिए उनका नाम हो गया वीर सावरकर। बालक सावरकर के बाबा विनायक और उनके पिता दामोदर दोनों महान देशभक्त थे। सावरकर जी को देशभक्ति विरासत में मिली थी। 1889 में छः वर्ष की अवस्था में बालक सावकरकर को पाठशाला भेजा गया। वे पढ़ने लिखने में बड़े तेज थे। उन्हें जो पढ़ाया जाता था, उसे कंठस्थ कर लिया करते थे। उनकी बुद्धि और प्रतिभा की प्रशंसा उनके अध्यापक भी करते थे। वे घर पर अपने माता–पिता से साहसी वीरों की कहानियां सुना करते थे। उनके एक अध्यापक ने कहा था कि यह बालक बड़ा होने पर एक महान वक्ता बनेगा। 1901 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सावरकर जी ने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया। वे कॉलेज में पढ़ते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया करते थे। लोकमान्य तिलक जी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। इसी काल

में सावरकर जी ने स्वतंत्रता के लिए एक योजना तैयार की – यह योजना थी–विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। इस योजना को तिलक जी का आशीर्वाद मिला। पूना से शुरू हुई विदेशी वस्त्रों की होली की लपटें पूरे भारत में फैलने लगी। ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी। सरकार के दबाव में सावरकर जी को कॉलेज से निकाल दिया गया।

बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् न तो उन्होंने नौकरी की, खोज की और न ही अपने घर ही गये। पूना में ही रहकर क्रांतिकारी दल का गठन करने लग गये। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने–कोने से दो सौ युवकों को पत्र लिखकर पूना बुलाया तथा उनके साथ गुपत स्थान पर बैठक की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान हमारा है। अंग्रेजों को हिन्दुस्तान पर राज्य करे का कोई अधिकार नहीं है। हमें चाहिए, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें। इसी बैठक में सबकी सलाह पर अभिनव भारत के नाम से नई संस्था का गठन किया गया। जिसका एकमात्र उद्देश्य था विद्रोह के द्वारा अंग्रेजी शासन को समूल नष्ट करना। इन्हीं दिनों 1906 में पूना में प्लेग फैल गया। सावरकर जी ने प्लेग पीड़ितों की घर–घर जाकर सेवा की। गरीबों के लिए भोजन और कपड़े का प्रबंध किया। गोरी सरकार को यह कार्य अच्छा नहीं लगा। सरकार सावरकर जी के कामों में बाधा उत्पन्न करने लगी। इससे युवकों का खून खौल उठा। परिणामत् पूना के अंग्रेज कमिश्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के अभियोग में चापेकर बंधु पकड़े गये, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा दी गई। सावरकर जी इससे उत्तेजित हो उठे। उन्होंने अपने साथियों का आह्वान किया कि जब तक चापेकर बंधुओं के खून का बदला नहीं लें तब तक चैन से नहीं बैठे। सावरकार जी को गिरफ्तार करन की योजना बनायी जाने लगी। इन्हीं दिनों सावरकर जी को इंग्लैंड में कानून पढ़ने के लिए श्याम कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिल गयी। 1906 में सावकर जी तिलक जी की सलाह पर इंग्लैंड चले गये। सावरकर जी 3 जुलाई 1906 को जब इंग्लैंड पहुंचे तो श्याम कृष्ण वर्मा ने उनका गरमजोशी से स्वागत किया। सावरकर जी उन्हीं के साथ इंडिया हाउस में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया। कुछ दिनों पश्चात श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस का कार्य सावरकर जी को सौंपकर स्वयं पेरिस चले गये। इसी दौरान सावरकर जी ने तीन पुस्तकें लिखीं। यद्यपि सावरकर जी इंडिया हाउस के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे। तथापि वे इससे संतुष्ट नहीं थे। भारत में अंगेजी शासन के विरूद्ध विद्रोह पैदा करने के लिए उनका मन व्याकुल हो रहा था।

अभिनव भारत में सावरकर जी के अतिरिक्त मदन लाल ढ़ींगरा सक्रिय थे। वह सावरकर जी के क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित थे।

उन्होंने एक दूसरी संस्था अभिनव भारत के नाम से गठित की। अभिनव भारत का एकमात्र उद्‌देश्य था भारत में विद्रोह की आग जलाना। इन सब कार्यों से सावरकर जी को प्रसिद्धि तो मिली लेकिन ब्रिटिश सरकार नाराज हो गयी। ब्रिटिश सरकार ने सावरकर जी को बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भी उन्हें प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया।

अभिनव भारत में सावरकर जी के अतिरिक्त मदन लाल ढ़ीगरा सक्रिय थे। वह सावरकर जी के क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित थे। 1909 में मदनलाल ढ़ींगरा ने इंग्लैंड में ही दिन दहाड़े एक अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। इस खबर से लंदन में सनसनी फैल गई। बायली की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए एक सभा की गई। सभा में जब श्री ढ़ींगरा की निंदा का प्रस्ताव रखा गया तो सावरकर जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा जब तक श्री ढ़ींगरा के मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का मत प्रकट करना गैरकानूनी है। सावरकर जी को इंग्लैंड में बम्बई के वारंट पर गिरफ्तार किया गया। वे जानते थे कि बम्बई में उन पर मुकदमा चलनेगा और मुकदमे में या तो फांसी की सजा होगी या आजीवन काले पानी की सजा। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी वे मार्ग में ही अंग्रेजों के पहले से निकल भागेंगे। योजना के अनुसार सावरकर जी फ्रांस के बंदरगाह मार्सलीज से थोड़ा पहले समुद्र में कूद पड़े तथा तैरकर मार्सलीज बंदरगाह तक पहुंच गये। लेकिन वहां पर एक फ्रांसिसी पुलिस मैन ने अंग्रेज सिपाहियों से कुछ रिश्वत लेकर सावरकर जी को उनके सुपुर्द कर दिया। फलतः वे कैदी बना लिये गये। बम्बई के हाईकोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा तीन माह तक चला। जजों ने अपने निर्णय में

कहा कि सावरकर को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, पर हमने उसकी युवा अवस्था को देखकर उन्हें 40 वर्ष के लिए काले पानी की कठोर सजा दी है। 1911 के अंत में सावरकर जी को सजा काटने के लिए अंडमान के कारागार में भेज दिया गया। वहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। उनके गले में 40 वर्ष कारावास का पट्टा देखकर जेलर ने उनसे पूछा क्या तुम 40 वर्ष की सजा काटने तक जीवित रह सकोगे? वीर सावरकर ने बिना विचलित हुए कहा, ''मैं तो जरूर जीवित रहूंगा, पर यह भी तय है कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ेग इतनी अवधि के पहले ही भारत से नेस्तनाबूद हो जायेंगी।'' 1911 से 1921 तक वे अंडमान की जेल में बंदी रहे। 1921 से 1926 तक अलीपुर की जेल में बंद रहे और 1926 में वे पूर्ण रूप से छोड़ दिए गये।

द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज युद्ध तो जीत गये लेकिन उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। अतः युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस से समझौता किया। फलस्वरूप सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता छोड़ दिए गये। अंग्रेज अखण्ड भारत को आजादी नहीं देना चाहते थे। वे मुस्लिम लीग की मांग पर पाकिस्तान भी बनाना चाहते थे। गांधी जी ने जिन्ना को मनाने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन जिन्ना नहीं माने। अतः गांधी जी को भी विवश होकर भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। वीर सावरकर ने ऊंचे स्वर से इस समझौते का विरोध किया। हिन्दू महासभा की ओर से जगह–जगह सभायें की गयी। समझौते के अनुसार 15 अगस्त 1947 कें दिन विभाजित भरत को स्वतंत्र कर दिया गया। दोनों तरफ सांप्रदायिक दंगे हुए। सावरकर जी ने पहले ही यह चेतावनी दी थी। सावरकर जी ने कहा पाकिस्तान बनने से हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए महान संकट उत्पन्न हुआ है। विभाजन से खिन्न हुए युवक नाथूराम गौड़से ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। गौडसे का संबंध सावरकर जी से जोड़ा गया। सावकर जी ने 59 पृष्ठों का बयान देकर यह सिद्ध किया कि गांधी जी की हत्या से उनका कोई संबंध नहीं है। जज महोदय ने उन्हें सम्मानपूर्वक गांधी जी की हत्या के अपराध से मुक्त कर दिया।

1949 के पश्चात सावकर जी राजनीति से पृथक होकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। 1957 में भारत के कई नगरों में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली की एक सभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा, ''आज तक जिस किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया उसे या तो काला पानी मिला या फांसी की सजा। इससे अधिक मैं किसी को कुछ दिला भी नहीं सकता। मुझे तो इसी बात की प्रसन्नता है कि मेरे जीवन में ही मेरा जीवन लक्ष्य पूरा हो गया। देश की स्वतंत्रता को अक्षुण रखना और इसे समृद्धि के शिखर पर पहुंचाना, आप लोगों का काम है।

1962 में भारत पर चीन ने तथा 1965 में पाकिस्तान ने दूसरी बार भारत पर आक्रमण किया। चीन के साथ युद्ध में भारत को नीचा देखने पर उन्होंने बड़ा दुःख प्रकट किया। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की विजय पर उन्होंने शास्त्री जी को बधाई दी। इन दिनों सावरकर जी रूग्ण शैया पर थे। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा इस प्रकार प्रकट की, ''मेरी मृत्यु पर न हड़ताल की जावे, न किसी कार्यक्रमम में बाधा डाली जाये, सिसे देश की हानि हो। मेरे श्राद्ध का धन बचाकर हिन्दू धार्मिक संस्थाओं को दान में दिया जाये।''

वीर सावरकर ने जीवन भर भारत की स्वतंत्रता तथा हिन्दू राष्ट्र के लिए बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। बड़ी–बड़ी यातनाएं सहन की, अपमान एवं कष्टों की आग में जले लेकिन उनकी जीवन ज्योति कभी भी धूमिल नहीं हुई। 26 फरवरी 1966 को वे महाकाल के गाल में समा गये।

द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज युद्ध तो जीत गये लेकिन उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। अतः युद्ध समाप्त होते ही अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस से समझौता किया।

सावरकर जी ने अंडमान से अपनी भाभी को लिए गये पत्र में लिखा था, मातृभूमि–तरे चरणों में मैं अपना मन अर्पण कर चुका हूं। मां तेरा कार्य ईश्वरीय कार्य है।

सावरकर जी जैसे महान देशभक्त की आजाद भारत में उपेक्षा हो रही है। हम सावरकर जी को भूलते जा रहे हैं। हम सावरकर जी के नाम की पट्टी तक हो विरोध करने लग गये हैं। सावरकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम युवकों में देशभक्ति का जज्बा जागृत करें एवं इस राष्ट्र को अखण्ड एवं सशक्त बनायें। सावरकर जी को भूलना न केवल उनकी उपेक्षा है, बल्कि इस महान राष्ट्र को पुनः गुलामी की ओर धकेलना होगा। ❑❑

आयुर्वेदः स्वस्थ्य एवं दीघार्यु जीवन पद्धति

आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। आयुर्वेद संस्कृत के 'आयु व वेद' दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु का अर्थ होता है– जीवन या उम्र तथा वेद का अर्थ होता है – ज्ञान। अर्थात् जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद भगवान द्वारा दिया गया एक विशेष उपहार है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बना सकते है। दुनिया के सबसे बड़े महाग्रंथ 'महाभारत' के रचियता महान संत श्री वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की। इन वेदों में जड़ी–बूटियों द्वारा रोगों के उपचार एवं स्वास्थ्य जीवन को दीर्घायु कैसे बनाएं, का विवरण स्पष्ट है।

वेद चार है– रिग वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थववेद। आयुर्वेद अर्थववेद की एक उपधारा है। सर्वप्रथम इस चिकित्सा पद्धति का ब्राह्मणों ने अध्ययन किया और इस पद्धति का रोगों के उपचार में प्रयोग हुआ। धीरे–धीरे समयानुसार इस चिकित्सा पद्धति को अन्य जाति/वर्ण के लोगों ने भी अध्ययन करना प्रारंभ किया तथा इसके द्वारा रोगों का निवारण करने लगे। 1500 ईस्वी पूर्व इस चिकित्सा पद्धति के प्रचलन में वृद्धि हुई। चीन, यूनान, तिब्बत, अफगानिस्तान, रोमन, मिस्र आदि देशों के लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए भारत आने लगे।

कुछ सदियों से (खासकर ब्रिटिश शासनकाल से) इस चिकित्सा पद्धति में गिरावट आई है। इस समयावधि में यह उपचार का प्रारंपरिक विकल्प न होकर द्वितीय विकल्प और गरीबों के उपचार का माध्यम बन कर रह गयी। वर्ष 1947 के बाद इस पद्धति का ओर ध्यान दिया जाने लगा तथा आयुर्वेद के संस्थान खोले जाने लगे।

मानव शरीर, तीन देहद्रव (वात, पित्त व कफ), सात बुनियादी उत्तकों (रासा, रक्ता, मानसा, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र) और शरीर के अपशिष्ट उत्पाद (मल) जैसे मल, मूत्र एवं पसीने का समूह है। शरीर के विकास एवं क्षय होने में इन सभी का विशेष महत्व होता

मनुष्य युवावस्था में दिनोंदिन अमीर बनने की चाह में अपना आरोग्य खो देता है और वद्धावस्था में उसी कमाए हुए धन से आरोग्य पाने के लिए असफल प्रयास करता है। जबकि वह जानता है कि धन से सुविधाएं अर्जित की जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। अगर हमें स्वस्थ्य एवं दीघार्यु जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन में आयुर्वेद (स्वदेशी) जीवन शैली एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता देनी होगी।

– **स्वदेशी संवाद**

है। भोजन के पाचन तथा पाचन के बाद बचे भोजन को मल में परिवर्तित इन्हीं देहद्रव एवं उत्तकों का काम होता है। इन देहद्रवों के असंतुलित होने से ही मानव शरीर में विकार (रोग) उत्पन्न होते है।

वात दोष वायु और अंतरिक्ष तत्वों से बना है। वात मन और शरीर की सभी क्रियाओं (रक्त प्रवाह, मल के उन्मूलन, श्वास और मन के विचारों आदि) को नियंत्रित करता है। पित और कफ इसके बिना कार्य नहीं करते, इसलिए वात को तीनों आयुर्वेदिक सिद्धांतों का मुखिया माना गया है। वात दोष फरवरी और अक्टूर माह में अधिक प्रभावी होता है। वात को संतुलित रखना बहुत ही आवश्यक होता है। आयुर्वेद में हर मौसम एक दोष बढ़ाता है– सदियों में वात, गर्मी में पित्त और वसंत में कफ।

वात के असंतुलन होने से अनियमित पाचन, चक्कर आना, अधिक चिंता होना, अधिक बैचेन या उत्तेजित होना, कब्ज, निद्रा न आना, भूलना, जोड़ों में असुविधा, जल्दी थकना आदि विकार उत्पन्न होते है। गर्म एवं पका हुआ भोजन वात दोष को शांत करने में महत्वपूर्ण कारक है। भोजन नियमित समय पर एवं नियमित करना, दोपहर का भोजन भारी और रात्रि का भोजन हल्का और सोने से कम से कम 3 घंटे पहले करना वात दोष को दूर करने में सहायक है।

पित मन और शरीर की सभी गर्मी, चयापचय तथा परिवर्तन को नियंत्रित जैसे भोजन को पचाना, संवेदी अनुभूति, तथा सही एवं गलत में भेद करना, करता है। पित के असंतुलन से मुख्यतः निराशा, चिड़चिड़ापन, त्वचा पर लाल चकत्ते, बालों के समय से पहले सफेद होना, दस्त आदि विकार उत्पन्न होते है। दूध, मक्खन और घी पित दोष को दूर रखने में सहायक होते है। ज्यादे मसालेदार, लाल मिर्च, एवं खट्टी वस्तुओं और फलों का कम सेवन पित दोष को शांत रखता है।

कफ शरीर और मन में स्नेहन (चिकनाहट) एवं संरचना जैसे वजन, विकास, जोड़ों एवं फेफड़ों में स्नेहन और सभी सात ऊत्तकों (पोषक तरल पदार्थ, रक्त, वसा, मांसपेशियां, हड्डियां, मज्जा और प्रजनन) के गठन को नियंत्रित करता है। इसके असंतुलन से मोटापा, सुस्ती, नाड़ी समस्या, शुष्क बाल एवं त्वचा, ठंड एवं नम मौसम में असुविधा, शरीर में सूजन आदि समस्याओं उत्पन्न होती है। कफ को संतुलित करने के लिए नित्य जल्दी सोना, जल्दी उठना और नित्य व्यायाम करना लाभप्रद है। भोजन में ताजे फल–सब्जियों का सेवन, तेल, भारी, ठंड़े पदार्थ, खट्टा एवं नमकीन का कम सेवन कफ को नियंत्रित करने में सहायक होते है।

आयुर्वेद को मुख्यतः दो भागों में बाटा जा सकता है। प्रथम, जीवन शैली तथा द्वितीय चिकित्सा पद्धति। अगर हम अपने जीवन में आयुर्वेद जीवन शैली (जैसे सोने–उठने का समय, नित्य व्यायाम, संतुलित भोजन आदि) को अपनाए तो हमारे शरीर में देहद्रव व उत्तकों का संतुलन बना रहता है और हम रोगों से दूर रह पाते है। प्राचीनकाल में इस जीवन शैली को प्राथमिक रूप में लिया जाता रहा है। लेकिन व्यस्तता एवं दिनोदिन अमीर बनने की चाह के चलते आज मानव अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता। जिसके कारण हम रोगों से ग्रस्त होते चले जाते है। जिसका निवारण भी हम जल्द से जल्द चाहते है। इस कारण हम विषम चिकित्सा पद्धति (एलोपैथी) को प्राथमिकता पर रखते है। उसके लिए हम अधिक व्यय भी करते है। जबकि आयुर्वेदिक जीवन पद्धति एवं चिकित्सा पद्धति में बहुत कम व्यय होता है।

धन से सुविधाएं अर्जित की जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं।

आज बड़ा प्रश्न यह है कि जिस देश ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया' का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया, आज उस भारत में चारों तरफ लोग बीमार क्यों हैं? आज बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसकर प्रतिवर्ष 6.4 करोड़ भारतीय गरीब हो रहे हैं। कारण–हम रहते तो भारत (समशीतोष्ण जलवायु) में है और जीवन शैली अपनाते है–यूरोप और अमरीका की। भारत का आरोग्य बीमा करने से नहीं, आयुर्वेद जीवन शैली/आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति/स्वदेशी चिकित्सा विज्ञान में है।

मनुष्य युवावस्था में दिनोंदिन अमीर बनने की चाह में अपना आरोग्य खो देता है और वृद्धावस्था में उसी कमाए हुए धन से आरोग्य पाने के लिए असफल प्रयास करता है। जबकि वह जानता है कि धन से सुविधाएं अर्जित की जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। अगर हमें स्वस्थ्य एवं दीघार्यु जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन में आयुर्वेद (स्वदेशी) जीवन शैली एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता देनी होगी। ❑❑

वाटर एटीएम बुझायेगा आपकी प्यास

देशभर में पेयजल संकट के बीच सार्वजनिक स्थलों पर अब जनजल वाटर एटीएम आपकी प्यास बुझाएगा। सुप्रीमअस समूह की तरफ से की जा रही इस पहल का उद्देश्य अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल, ग्राम पंचायत, कस्बों, शहरों, महानगरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पेयजल की सुविधा प्रदान करना है। रेलवे स्टेशनों पर यात्री मुफ्त में पेयजल प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि पानी का एटीएम जनजल अन्य स्थानों पर मामूली लागत पर 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक जनजल एटीएम की क्षमता प्रतिदिन 20,000 लीटर सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की है। इसके जरिये कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा जिन्हें इससे संबंधित प्रणालियों के परिचालन के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इस एटीएम की प्रणाली बिना बिजली के परिचालित होती है।

टायकून ने खरीदा टाटा का स्कॉटलैंड प्लांट

यूके (यूनाईटिड किंगडम) में रहने

वाले इंडियन स्टील टायकून संजीव गुप्ता ने टाटा स्टील का स्कॉटलैंड में मौजूद प्लांट को खरीद लिया है। टाटा स्टील ने इंग्लैंड का पूरा बिजनेस बेचने का एलान किया था। गुप्ता को इंग्लैंड की स्टील इंडस्ट्री को बचाने वाला कहा जाता है। संजीव कुमार गुप्ता (एसकेजी) मुलतः पंजाब के रहने वाले है।

360 अरब डालर हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व

देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 अप्रैल 2016 को 420 करोड़ रुपए बढ़कर 359.75 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पहले 25 मार्च को समाप्त सप्ताह में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 355.56 अरब डॉलर था। रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सबसे बड़ा सोर्स फॉरेन करेंसी एसेट्स 335.68 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसमें एक सप्ताह के दौरान 353 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

महा बैंक बनाने की तैयारी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दशा व दिशा तय करने के लिए गठित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की पहली बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में देश में मौजूदा 22 सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर सिर्फ छह या सात रखने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बीबीबी के अध्यक्ष विनोद राय और वित्त राय मंत्री जयंत सिन्हा की अगुवाई में हुई इस बैठक में

यह आम राय थी कि इस बारे में अभी तक जितनी सरकारी समितियों की रिपोर्ट आई हैं, उनका अध्ययन किया जाए और आगे का रोड मैप बनाया जाए। सरकारी बैंकों के विलय पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में यह मंशा साफ कर दी थी कि वह महा बैंक बनाने की प्रक्रिया को अब यादा दिनों तक नहीं टालेंगे। अभी तक सरकार यह कह रही थी कि इस बारे में पहल बैंकों को ही करनी होगी लेकिन बैंकों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आने पर अब इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बीबीबी को सौंप दी गई है।

स्पीड पोस्ट का बदला मॉडल

बिजनेस के बदलते ट्रेंड को देखते हुए इंडिया पोस्ट ने अपने स्पीड पोस्ट के बिजनेस मॉडल में अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों के जरिए डिपार्टमेंट की कोशिश बढ़ते ई–कॉमर्स सेग्मेंट और कस्टमर की बदलती डिमांड पूरा करने की है। अब डिपार्टमेंट का फोकस नई टेक्नोलॉजी के जरिए फास्ट डिलिवरी पर होगा। ई–कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन सेलर्स के लिए कैश ऑन डिलिवरी, इंटरनेट के जरिए टैक

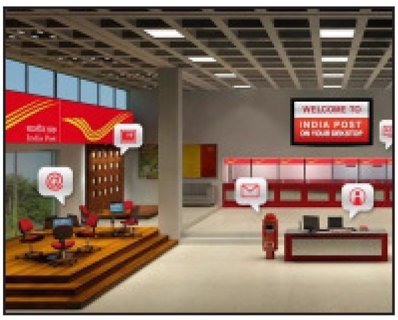

और ट्रेस सिस्टम, डिलिवरी होने पर भेजने वाले के पास एसएमएस अलर्ट, बल्क डिलिवरी पर फ्री पिकअप सर्विस, पहले बुकिंग और डिलिवरी के बाद पेमेंट सर्विस, देश के प्रमुख शहरों में 24 घंटे बुकिंग की सुविधा, वॉल्युम के आधार पर कस्टमर को डिस्काउंट, डिलिवरी की इन्श्योरेंस सर्विस एक्सट्रा चार्ज देने पर उपलब्ध आदि मुख्य बदवाल होंगे।

एनएफसी ने परमाणु ईंधन में बनाया विश्व रिकॉर्ड

हैदराबाद स्थित न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स (एनएफसी) ने बीते वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 1503 मीट्रिक टन परमाणु ईंधन का उत्पादन कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2014–15 में एनएफसी ने 1252 टन का उत्पादन कर दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ईंधन उत्पादक का तमगा पाया था। फिलहाल देश को 750 टन परमाणु ईंधन की ही जरूरत पड़ती है।

रेलवे को 8 लाख करोड़ का नेशनल प्लान

मोदी सरकार रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए करीब 8.5 लाख करोड़ रूपये का ठोस इन्वेस्टमेंट प्लान बना रही है। इस स्कीम में– फंडिग का एक बड़ा हिस्सा पीपीपी और मल्टीलेटरल फंडिंग के जरिए आ सकता है, रेल डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्पेंडिचर एक हिस्सा रेल बजट से मिलेगा, कोऑपरेशन के लिए 13 देशों के साथ एग्रीमेंट, मुंबई–अहमदाबाद हाई–स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान के साथ लगभग 97 हजार करोड़ की डील, रेल एक्सपेंशन के लिए एलआईसी 1.5 लाख करोड़ रूपये का कर्ज देगी आदि शामिल है।

दूध में मिलावट पर लगेगी लगाम

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) 60 वर्षों के बाद मिल्क सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने जा रहा है। इससे दूध में मिलावट की बढ़ती घटनाओं को रोकना संभव होगा। FSSAI के अनुसार, देश में उत्पादित 68 फीसदी दूध में मिलावट होती है। दूध में अमूमन रिफाइंड ऑयल, कॉस्टिक सोडा, सफेद पेंट और डिटर्जेंट मिलाने

के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में संगठन का यह कदम बेहद असरदार साबित हो सकता है। दूध में मिलावट की जांच के लिए एक स्कैनर तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए 40 सेकंड में दूध की मिलावट की जांच हो जाएगी। एक सैंपल की जांच में 10 पैसें के बराबर ही खर्च आएगा। जल्द ही यह स्कैनर जिले स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें अलग से केमिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, सिंगल स्कैनर से मिलावट की पहचान कर ली जाएगी।

भारत मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2014–15 में ग्लोबल प्रोडक्शन में 18.5 फीसदी का योगदान किया। इकोनॉमिक सर्वे 2015–16 के मुताबिक, 2013–14 की तुलना में 2014–15 में दूध का उत्पादन 6.26 फीसदी बढ़ गया है। 2014–15 में उत्पादन 14.63 करोड़ टन रहा, जबकि 2013–14 में उत्पादन 13.76 करोड़ टन था। भारत में प्रति व्यक्ति 322 ग्राम दूध प्रति दिन उपलब्ध है, जबकि 1990–91 में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 176 ग्राम थी। यह पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति औसत 294 ग्राम दूध की उपलब्धता से ज्यादा है।

पंखों वाला स्कूटर

स्कूटर आज ऑटोमोबाइल की दुनिया में मोटरसाइकिलों की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं, वहीं वाहन निर्माता अपना सर्वश्रेष्ठ मॉडल प्रदान करने के प्रयासों पर जोर दे रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यामाहा मोटर ने हाल ही में 2016 वियतनाम मोटर साइकिल शो में 04GEN कॉन्सेप्ट को शोकेस किया है। स्कूटर का मुख्य आकर्षण अर्द्ध पारदर्शी पंख हैं जो चेसिस को कवर करते हैं।

फेसबुक पर लाईव वीडियो प्रसारण

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपने सभी यूजर के लिए लाइव वीडियो शेयरिंग सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस फीचर के तहत

लोग अपने फोन से फेसबुक पर टीवी की तरह लाइव वीडियो का प्रसारण कर सकेंगे। फेसबुक की मोबाइल एप पर जहां पहले मैसेंजर का बटन दिखता था। अब वहां लाइव वीडियो का बटन दिखाई देगा। फेसबुक के इस फीचर के तहत जैसे ही कोई व्यक्ति लाइव वीडियो के विकल्प पर क्लिक करेगा तो फोन का कैमरा खुल जाएगा। यहां पोस्ट के विकल्प पर क्लिक करते ही कैमरे के सामने का नजारा फेसबुक पर रियल टाइम में शेयर होने लगेगा। इस फीचर के तहत जब भी कोई आपका दोस्त लाइव वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देगा तो फोटो के साथ उसकी कमेंट भी रियल टाइम में देखी जा सकेगी।

क्या है 'टैक्स हैवन'

एक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि कई बड़े नेताओं ने विदेशों में कालाधन जमा कर रखा है। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का परिवार, पाकिस्तानी प्रधामंत्री और कई देश के राष्ट्राध्यक्षों के नाम शामिल हैं। इसमें बॉलीवुड के मशहूर सितारे अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या रॉय बच्चन और रीयल इस्टेट टायकून केपी सिंह, मृतक गैंगस्टर इकबाल मिर्ची समेत 500 भारतीयों के नाम भी हैं।

जांच के लिए समिति ने पनामा स्थित 'मोजाक फोंसेका' नामक एक कंपनी के दस्तावेजों का सहारा लिया जो दुनिया भर के कई बड़े और नामचीन लोगों के पैसों को छिपाने में उनकी मदद करती है। इसमें कंपनी के करीब 214,000 दस्तावेज शामिल थे।

टैक्स हैवन देश ऐसे देश होते हैं जहां पर पैसे जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगता या बहुत ही कम टैक्स लगता है। ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते न ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। ये देश उन लोगों के लिए स्वर्ग (हैवन) हैं, जो टैक्स चोरी करके पैसे इन देशों में जमा कर देते हैं। जिसमें–लक्समबर्ग, केमैन आइलैंड्स, आइल ऑफ मैन, जसी, आयरलैंड, मॉरिशस, बरमूडा, मोनैको, स्विटजरलैंड, बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड प्रमुख देश शामिल है।

विदेशों में भारत से कालाधन न जा सके इसके लिए फरवरी 2004 में एक स्कीम शुरू की गई, जिसका नाम

लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम था। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति विदेशों में हर साल सिर्फ 25 हजार डॉलर (करीब 13.23 लाख रु) की राशि ही भेज सकता था, वो भी दिए दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए। इन दिशा निर्देशों के तहत कोई भी व्यक्ति विदेश में पढ़ाई, घूमने, चिकित्सा या फिर किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भेज सकता था। सितंबर 2007 में यह सीमा बढ़ाकर 2,00,000 डॉलर कर दी गई। हालांकि अगस्त 2013 में फिर से इसे कम करते हुए 75,000 डॉलर कर दिया गया। यह कटौती रुपए में आई भारी गिरावट के मद्देनजर की गई थी। कुछ समय बाद फिर से इसे बढ़ाकर 2,50,000 डॉलर (करीब 1.65 करोड़ रु) कर दिया गया। यह पैसे विदेश में रह रहे किसी रिश्तेदार या दोस्त को खर्च के लिए, तोहफे में या दान के रूप में भी भेजे जा सकते हैं।

सस्ती हुई रसोई गैस

तेल कंपनियों ने 14.2 किलो ग्राम गैस वाले गैर सब्सिडी शुदा एलपीजी सिलेंडर की कीमत में चार रुपए प्रति की कटौती की है। उपभोक्ताओं को

सालाना 12 सिलेंडर का सब्सिडी का कोटा खत्म होने पर ये सिलिंडर लेने होते हैं। गैर सब्सिडी गैस की कीमत अब दिल्ली में 509.50 रुपए होगी जो पहले 513.50 रुपए प्रति सिलेंडर थी। यह लगातार तीसरा मौका जब कि सिलेंडरों की कीमत में कटौती की गई है। इससे पहले कीमत एक मार्च को 61.50 रुपए घटाई गई थी। सब्सिडीशुदा रसोई गैस की लागत दिल्ली में 419.33 रुपए प्रति सिलेंडर है।

सौर ऊर्जा 48,000 मेगावाट करने का लक्ष्य

सरकार की 2019 की शुरूआत तक सौर बिजली उत्पादन बढ़ाकर 48,000 मेगावाट करने की योजना है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत स्वच्छ ऊर्जा स्रोत से 1,00,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में अक्षय ऊर्जा स्रोत से 12,000 मेगावाट तथा 2017–18 तथा 2018–19 तक 15,000

मेगावाट तथा 16,000 मेगावाट क्षमता इजाफा का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में 2,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। 7 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार देश में सौर बिजली उत्पादन क्षमता 5,775.57 मेगावाट थी। हालांकि 2018–19 के बाद अगले तीन वर्ष में कुल क्षमता में 52,000 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन जोड़ना होगा क्योंकि 2021–22 राष्ट्रीय सौर मिशन का अंतिम वर्ष होगा। मंत्रालय ने 2022 तक 1,00,000 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिये 2019–20 में 17,000 मेगावाट, 2020–21 तथा 2021–22 में 17,500–17,500 मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य रखा है। सरकार का अनुमान है कि 1,00,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करने में करीब 6.0 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। सौर परियोजनाएं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दोनों लगा रही हैं।

ज्वैलर्स की हड़ताल समाप्त

41 दिनों से चली आ रही ज्वैलर्स की हड़ताल दिनांक 12 मार्च 2016 को समाप्त हो गई है। दिल्ली, मुंबई समेत करीब–करीब देश के ज्यादातर बड़े शहरों में ज्वैलर्स ने हड़ताल समाप्त कर दुकानों पर कारोबार शुरू कर दिया है। ज्वैलर्स पिछले 41 दिन से एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। वित्तमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि दुकानों पर इंसपेक्टर राज वापस नहीं आएगा। इसके लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक हेल्पलाइन

जारी करने का भरोसा दिया है। वित्तमंत्री के इस भरोसे के बाद ज्वैलर्स ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। 41 दिनों की इस हड़ताल से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस नुकसान हो चुका है।

IIT की फीस दुगानी से भी ज्यादा करने का प्रस्ताव

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के स्नातक पाठ्यक्रमों की फीस दोगुनी से ज्यादा करने का प्रस्ताव किया है। इस साल से शुरू होने वाले सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा। उन्हें अब 90 हजार की जगह दो लाख की सालाना फीस देनी होगी। इसके साथ ही मंत्रालय के प्रस्ताव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (जिनकी सालाना आय एक लाख से कम है) के छात्रों की फीस माफ कर दी गई है। जबकि पांच लाख से कम आय वर्ग के लिए फीस में दो तिहाई की छूट का प्रावधान है।

नीता अंबानी एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला

रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबनी को फोर्ब्स ने एशियाई की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी करार दिया है जो इस क्षेत्र की 50 प्रमुख उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर हैं। इस सूची में 8 भारतीय महिलाओं ने स्थान बनाया है। एसबीआई की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरुणधती भट्टाचार्य

को 2016 की 'एशिया की 50 शक्तिशाली महिला कारोबारी' की सूची में दूसरा स्थान दिया गया है जिसमें चीन, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाइलैंड, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, फिलिपीन और न्यूजीलैंड की प्रभावशाली महिलाएं शामिल हैं। फोर्ब्स ने कहा, इस सूची में स्वीकार किया गया है कि कारोबारी दुनिया में महिलाएं अपनी जगह बना रही हैं लेकिन स्त्री–पुरुष असमानता बरकरार है। महिलाएं यह समझने की बेहतर स्थिति में हैं कि उन्हें नेतृत्व की स्थिति में आने और वहां बने रहने के लिए क्या करना होगा।

आरबीएस होगा भारत में बंद

रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस) भारत में कॉरपोरेट बैंकिंग ऑपरेशंस बंद करेगा। वह दुनिया भर के कई देशों में संचालन कर रहा है। उनमें से दो–तिहाई में बैंक की कारोबार समेटने की योजना है। इस साल के शुरू में यूनिट को खरीदने के लिए सिंगापुर का डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स और दक्षिण अफ्रीकी बैंकिंग ग्रुप फर्स्टरैंड आरबीएस के साथ अलग–अलग बातचीत कर रहे थे। बीते साल आरबीएस के सीईओ रॉस मैकईवान ने 38 के बजाय 13 देशों में संचालन करने की रणनीति का एलान किया था। ❑❑

RBS
The Royal Bank of Scotland

देशघातक बुद्धूजीवियों के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन एवं पुतला दहन, नई दिल्ली

स्वदेशी जागरण मंच, दिल्ली प्रांत द्वारा दिनांक 22 मार्च 2016 को मंडी हाउस से जंतर–मंतर तक पैदल मार्च निकाला गया तथा राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल बुद्धूजीवियों के पुतलों का दहन भी किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) श्री वी.एम. पाटिल, ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा, ग्रुप कैप्टेन विजय वीर आदि कई पूर्व सैन्य अधिकारी, जे.एन.यू. एंव दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्राध्यापकों, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री अश्वनी महाजन, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री प्रदीप शर्मा, दिल्ली एवं हरियाणा प्रात संगठक श्री कमलजीत, दिल्ली प्रांत संयोजक श्री सुशील पांचाल ने किया। साथ ही कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे।

श्री एन.एस. मलिक व लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) श्री वी.एम. पाटिल ने मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना विश्व की सर्वाधिक अनुशासित सेनाओं में से एक है। हमारी सेना विषम परिस्थितियों में भी न केवल सीमाओं की रक्षा करती है वरन् देश में आने वाली आपदाओं में भी देशहित के लिए धैर्यपूर्वक कार्य करती है। ऐसी स्थिति में जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष जो कि स्वयं एक अपराध में जमानत पर छूटे हुए है उनके द्वारा सुरक्षा बलों पर निराधार आरोप लगाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कडे शब्दों में निंदा की जानी चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान चर्चों पर हमले की झूठी खबरें चलाई गई। चुनाव खत्म, खबर खत्म। ठीक उसी प्रकार बिहार चुनाव के दौरान असहिष्णुता का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, चाहे अवार्ड वापसी हो या न्यूज चैनल हो, सभी माध्यमों को कुप्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में बंगाल में चुनाव है, जेएनयू का मामला राजनीति साजिश के तहत सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अफजल गुरू कौन था? वह कोई साधारण अपराधी नही था। उसके इरादे ओसामा बिन लादेन से भी खतरनाक थे। ओसामा ने तो केवल अमेरिका में बिल्डिंग ही उडाई थी, किन्तु अफजल गुरु भारत के लोकतंत्र के मंदिर में घुसकर समूचे पक्ष व विपक्ष के नेताओं को मारकर महान भारत देश को नेतृत्वविहीन करना चाहता था। यह कोई साधारण घटना नही थी। पूरे देश को अराजक माहौल में धकेलने की उसकी साजिश थी। ऐसे देशद्रोही की बरसी जेएनयू में मनाया जाना, किसी भी रूप में मान्य नही है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कन्हैया कर रहा था। जो इंगित करता है कि वह जेहादियों और वामपंथी लोगों का बौद्धिक आत्मघाती हमलावर (Intellectual suicide bomber) है। जो इस देश के टुकडे करना चाहते हैं। इस पूरे खेल में कांग्रेस भी शामिल है। स्वदेशी जागरण मंच पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करता है। क्योंकि यह आराजकता की ओर ले जाएगा। यदि वास्तव में कोई रास्ता है तो वह है 'स्वदेशी' एवं 'विकेन्द्रीकरण'।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. अश्वनी महाजन ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देशद्रोही गतिविधियों का अड्डा बनने की इजाजत नही दी जा सकती।

जेएनयू प्रोफेसर श्री शतेन्द्र शर्मा ने कहा कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अधिकांश छात्र देशभक्त एंव प्रतिभाशाली है। जिहादी तत्व एवं घोर वामपंथी तत्व कुछ छात्रों को भटकाकर उनका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए करते हैं। जेएनयू राष्ट्रवादी शिक्षक एवं छात्र ऐसे तत्वों को कभी भी अपनी घृणित चालों में सफल नही होने देगें।

दिल्ली हरियाणा प्रांत संगठक श्री कमलजीत ने कहा कि जेएनयू में कुछ छात्रों ने जो नारे लगाए वह न केवल राष्ट्रद्रोह है बल्कि अफजल की फांसी की ज्यूडिशियल किंलिग कहना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान भी है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए।

मंच के दिल्ली प्रांत संयोजक श्री सुशील पांचाल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के अध्यक्ष श्री जमशेद आलम, श्री जितेन्द्र महाजन पूर्व विधायक, कमल तिवारी दिल्ली प्रांत सह संयोजक, रविन्द्र सोलंकी दिल्ली प्रांत सह संयोजक ने भी सभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर श्री मनोज गुप्ता, श्री दीपक त्यागी, श्रीमती मीना अरोडा, श्री यशवंत चौहान, श्री अभयराम, श्री रामकरण, श्री ताराचंद उपाध्याय, श्री राजीव मिश्र, श्री शशि तलवार, सुश्री ज्योति सैनी आदि सैकडों स्वदेशी कार्यकर्त्ता, समाजसेवी एवं बुद्धिजीवी शामिल थे। ❑❑